● वर्ष-3
● अंक-82
रायपुर, रविवार
12 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

अवकाश सूचना

दीपोत्सव पर्व के अवसर पर समाचार पचीसा के कार्यलय में 12 नवंबर, रविवार अवकाश रहेगा। समाचार पचीसा का अगला अंक 14 नवंबर, मंगलवार को प्रकाशित होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा में दिया बड़ा बयान

कांग्रेस सरकार में वामपंथी उग्रवाद: राजनाथ सिंह

कोरिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राजनाथ सिंह ने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली में आरोप लगाया कि मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वामपंथी उग्रवाद बढ़ा है। अगर भाजपा सत्ता में आई तो इसे तीन-चार वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई तो धर्मांतरण (जबरन) पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या हुआ वो आप जानते हैं...ऐसी भूखी और भ्रष्ट सरकार आपने कभी नहीं देखी होगी...अब महादेव जी आ गए हैं और लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भाजपा सरकार यहां आनी चाहिए।

कथित घोटालों को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकार ने राज्य में एक भी विकास कार्य नहीं किया है। अगर जनता से इस सरकार का रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए तो रिपोर्ट कार्ड में जीरो बटे सन्नाटा होगा। उन्होंने सत्तारूढ़ कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा, वे अच्छी सरकार देने में शून्य हैं और विकास करने में शून्य हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कांग्रेस नेता खुद

को हीरो बताते हैं. वे हीरो नहीं हैं. वे शून्य हैं. उन्हें चुनाव में विदाई देने का समय आ गया है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, मुझे पता चला है कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है, जो चिंता का विषय भी है। किसी को लालच देकर धर्म परिवर्तन क्यों कराया जाए? अगर बीजेपी सत्ता में आई तो हम इस तरह के धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगा देंगे।

सिंह ने आरोप लगाया कि 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई। उन्होंने कहा कि हत्या जैसे अपराध आम बात हो गए हैं। कई परिवारों की बेटियां गायब हो गई हैं जो एक बड़ी चुनौती है। मानव तस्करी और नशीली दवाओं का व्यापार बढ़ रहा है। प्रदेश से कांग्रेस को उखाड़ फेंकना जरूरी हो गया है। भाजपा ने पूर्व सीआरपीएफ कर्मी राम कुमार टोप्पो को कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा राज्य मंत्री अमरजीत भगत के खिलाफ सीतापुर सीट से मैदान में उतारा है।

घोटालों से कांग्रेस का मुंह और हाथ दोनों काला

राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया है। दूसरे का हक छीनकर अपने बेटे बेटियों को अफसर बना दिया। ऐसी सरकार को बदलने की जरूरत है। राजनाथ बोले की हम जब सरकार में आएंगे तो पीएसएसी घोटाले से जुड़े लोगों को जेल भेजेंगे। धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है उसे हमारी सरकार बनते ही पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने 2000 करोड़ का घोटाला शराब में किया है उनको हम किसी कीमत पर बाहर नहीं रहने देंगे।

गांधी परिवार को निशाने पर लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस बघेल सरकार को ये लोग हीरो करार दे रहे हैं। ये घोटालों की सरकार जनता की नजरों में हीरो नहीं जीरो है। राजनाथ बोले कि जब सीतापुर विधानसभा सीट से एक पूर्व सैनिक को टिकट मिला है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक पूर्व सैनिक के प्रचार के लिए देश का रक्षा मंत्री नहीं पहुंचता ये कैसे हो सकता है। रामकुमार टोप्पो अच्छा बोलते हैं और अच्छा दिखते भी इनको जरूर जिताएं। चुनावी रण में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की बारिश बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है उससे दूसरे चरण का प्रचार दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। राजनाथ का आरोप और उनकी अपील कितना असर क्षेत्र की जनता के बीच दिखाती है ये नतीजों के वक्त दिखेगा। 17 तारीख को होने वाले मतदान में अभी वक्त है, लिहाजा सियासी पारा अभी और चढ़ेगा। सियासी पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ेगा।

हमारी सरकार बनेगी तो देखते हैं कौन कराएगा धर्मांतरण

भाजपा के प्रचार के लिए स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सरगुजा संभाग में धुआंधार प्रचार किये. इस दौरान कोरिया जिले के सोनहत के सलगांवकला में आम सभा में राजनाथ सिंह ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि धर्मांतरण का दौर चल रहा है. यहां पर जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी हम देखते है किसने मां का दूध पिया है जो किसी का धर्मांतरण करवा देगा. हम किसी भी स्तर पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे. बता दें कि भरतपुर-सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी रेणुका सिंह के पक्ष में आमसभा को संबोधित करते उन्होंने ये बयान दिया है.

दौसा नाबालिग बलात्कार मामले को लेकर भाजपा ने गहलोत सरकार को घेरा

नईदिल्ली। दौसा नाबालिग बलात्कार मामले को लेकर भाजपा ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा पर निशाना साधा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गहलोत सरकार की निष्क्रियता, निकम्मेपन और नाकारापन से भरी हुई सरकार के चलते आज राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत और पूरी

मानवता को शर्मसार करने वाला एक कृत्य राजस्थान से सामने आया है। एक दलित परिवार की खुशी छीनने और कुकर्म का विभत्स कार्य गहलोत सरकार की वजह से वहां हुआ है। भाजपा नेता ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि जब राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वहां की महिलाएं जाएं कहां? दौसा में एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ राजस्थान पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर बर्बरतापूर्वक बलात्कार का घिनौना और हैवानियत भरा कृत्य करता है। लेकिन राजस्थान सरकार इस पर कार्रवाई करने की बजाय अपराधी के बचाव में लग जाती है। उन्होंने कहा कि दौसा की इस घटना के बाद वहां स्नद्धक्रतक दर्ज नहीं की गई, जबकि ये पॉक्सो का मामला है। भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के वहां प्रदर्शन करने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। देश भर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेटी बचाओ का आंदोलन चलाते हैं।जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कहीं भी महिलाओं का उत्पीड़न शर्मनाक है। गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देख लीजिए...लेकिन राजस्थान का मुद्दा उठाते हैं।

दीपोत्सव 2023 में इस बार नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दीपोत्सव कार्यक्रम में 22 लाख 23 हजार दिए जलाए गए। पहले 18 लाख 81 हजार दिए जलाए जाने का रिकॉर्ड था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट दिया गया है।

देश विकास के अहम मोड़ पर खड़ा है: मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना चुनाव को लेकर सिकंदराबाद में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आपने देश में कई सरकारें देखी हैं, हमारी सरकार ऐसी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब कल्याण, वंचितों को वरीयता देना है, भाजपा जिस मंत्र पर चलती है वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उन्होंने कहा कि मैं मादिगा समुदाय के लोगों से कहूंगा कि आपको जितना क्क्रस से सतर्क रहना है उतना ही कांग्रेस से सावधान रहना है। क्क्रस दलित विरोधी और कांग्रेस भी इसमें कम नहीं है। क्क्रस ने नए संविधान की मांग करके बाबा साहब का अपमान किया और कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है।

मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के कारण ही दशकों तक बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीबों का कल्याण और वंचितों को प्राथमिकता है। हम सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हम

श्री गुर्रम जशुवा और उनके सामाजिक न्याय के कार्यों को अपनी प्रेरणा मानते हैं। अपने साहित्य में उन्होंने एक दलित भाई का चित्रण किया है जिसने अपनी दुर्दशा बाबा विश्वनाथ से साझा की थी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले यहां बनी सरकार तेलंगाना के गौरव और सम्मान की रक्षा करने में सक्षम नहीं थी। दुनिया तेलंगाना के लोगों की क्षमताओं की सराहना करती है। हालाँकि, तेलंगाना सरकार ने लोगों को निराश किया है। इन दस वर्षों में, तेलंगाना सरकार ने मडिगा समुदाय सहित सभी को धोखा दिया।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन 10 वर्षों में, तेलंगाना सरकार ने केवल मडिगा समुदाय सहित सभी को धोखा दिया है। जब तेलंगाना बनने वाला था तब कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए लेकिन जब इतने बलिदानों के बाद तेलंगाना बना तो बीआरएस नेता आप लोगों को भूल गए और जाकर कांग्रेस नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान आपसे वादा किया गया था कि किसी दलित व्यक्ति को तेलंगाना का सीएम बनाया जाएगा लेकिन राज्य बनने के बाद केसीआर दलित लोगों के सपनों को कुचलकर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए।

प्रमुख समाचार

आतंकी एजेंडा बढ़ाने के लिए हासिल किए जाली दस्तावेज

अहमदाबाद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को गुजरात की विशेष अदालत में चार बांग्लादेशी नागरिकों समेत पांच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। ये सभी आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हैं। इन पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। आरोपपत्र में मोहम्मद सोजिब मियां, मुन्ना खालिद अंसारी उर्फ मुन्ना खान, जहांगीर उर्फ अजहरुल इस्लाम, अब्दुल लतीफ उर्फ मोमिनुल अंसारी और फरीद हैं। आरोप पत्र के अनुसार, सोजिब मियां, मुन्ना खान, जहांगीर और अब्दुल लतीफ बांग्लादेश के नागरिक हैं, जिन्होंने देश के भीतर गुप्त रूप से काम करने और अपने आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जाली दस्तावेज हासिल किए थे। मई में, गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था और बांग्लादेश के चार नागरिकों को गिरफ्तार किया था, जो फर्जी पहचान दस्तावेज का उपयोग करके भारत में प्रवेश करने के बाद अहमदाबाद में अवैध रूप से रह रहे थे। एनआईए ने जून में यूएपीए की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।

खत्म होने जा रहा 500 वर्षों का इंतजार, राम लला आ रहे हैं

नईदिल्ली। अयोध्या शहर दिवाली की पूर्व संध्या पर आज (11 नवंबर) एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करने के लिए तैयार है, जिसमें 51 घाटों

पर 24 लाख से अधिक दीये बड़ी संख्या में रोशन किए जाएंगे। उत्सव के तहत दीपोत्सव 2023 के लिए श्री राम जन्मभूमि पथ को भी विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जा रहा है। दीपोत्सव से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया और राजाभिषेक में हिस्सा लिया। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राम कथा पार्क के पास भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्रण करने वाले कलाकारों का स्वागत किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने दीप प्रज्वल को रेखांकित किया है। हमारी पीढ़ी बेहद सौभाग्यशाली है कि भगवान राम लला यहां विराजने के लिए आ रहे हैं। योगी ने कहा कि अयोध्या वासियों को भगवान राम ने खुद कहा है वे उनके प्रिय वासी हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब भगवान आ रहे हों तो 22 जनवरी को विराजमान करने के लिए उनके स्वागत की भव्य तैयारी करने के लिए खुद को तैयार रखना होगा।

परिवार पहले और राष्ट्र को बाद में पसंद करती है कांग्रेस पाटी

नईदिल्ली। असम कांग्रेस के नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सदस्य पोरीतुश रॉय ने शनिवार को यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि सबसे पुरानी पार्टी केवल नीले खून वाले लोगों का पक्ष ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित अपने इस्तीफे पत्र में, रॉय, जो असम प्रदेश युवा कांग्रेस (एपीवाईसी) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ने कहा, ॅमैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस संगठन में बने नहीं रह पाऊंगा। यह केवल नीले रक्त वाले लोगों का पक्ष ले रहा है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस संगठन में हम जैसे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, जो समाज के निचले तबके से आते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रॉय ने कहा कि कांग्रेस परिवार को पहले और राष्ट्र को बाद में पसंद करती है। उन्होंने कहा कि इस संगठन में काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि, दिसपुर से दिल्ली तक, यह संगठन पहले परिवार और बाद में देश को प्राथमिकता देता है। अतः इस संगठन में काम करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया है और इससे देश की आम जनता के हित खतरे में पड़ जायेंगे।

गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चे की मौत

संयुक्त राष्ट्र । विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रेयसस ने संयुक्त राष्ट्र

सुरक्षा परिषद (संरासुप) की आपात बैठक में कहा कि गाजा में कहीं भी और कोई भी सुरक्षित नहीं है और यहां स्वास्थ्य प्रणाली अपने घुटनों पर है।डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने शुक्रवार को आयोजित बैठक में कहा कि जमीनी स्तर पर स्थिति गंभीर है तथा अस्पतालों में बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करने से लेकर हर दस मिनट में एक बच्चे की मौत होने तक स्थिति अत्यंत गंभीर है।उन्होंने जोर देते हुए कहा, कहीं भी और कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा कर्मचारी 23 लाख लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टेड्रोस ने कहा कि समर्थन दिखाने का सबसे अच्छा तरीका स्वास्थ्य कर्मियों को जीवन बचाने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करना है। लगभग 63 मीट्रिक टन ऐसी सहायता भेजी जा चुकी है, लेकिन उन नागरिकों तक पहुंचने के लिए निर्वाध पहुँच की आवश्यकता है जो संकट के लिए जिम्मेदार नहीं है।

श्रीनगर में हादसा, डल झील की हाउसबोटों में लगी भीषण आग

जम्मू। श्रीनगर से इस समय एक दर्दनाक खबर आ रही हैं। श्रीनगर की डल झील में हाउसबोटों में

भीषण आग लगने से 3 पर्यटकों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी को अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को श्रीनगर की डल झील में भीषण आग लग गई और आग में जले हाउसबोट से तीन शव बरामद किए गए।अधिकारियों के मुताबिक, जले हुए शवों की पहचान की जा रही है और मृतकों में एक पुरुष और एक महिला शामिल हैं। तीसरे पीड़ित के लिंग का अभी तक पता नहीं चल सका है। आग से पांच हाउसबोट और उनसे जुड़ी इतनी ही संख्या में झोपड़ियां समेत करोड़ों रुपये की संपत्ति भी नष्ट हो गई। स्टेशन हाउस ऑफिसर फायर सर्विस, फारूक अहमद ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि कुछ पर्यटकों को बचाया गया और कॉल मिलते ही बचाव अभियान शुरू हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने श्रीनगर में जिला मुख्यालय से और अधिक जनशक्ति मांगी है। एक हाउसबोट में लगी आग तेजी से फैल गई और कई अन्य को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के कारण का तत्काल पता नहीं चल पाया है।

मप्र चुनाव

भाजपा ने गेहूं-धान के लिए ऊंची एमएसपी,

लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों को आवास का किया वादा

उन्होंने कहा कि पार्टी की 11,000 किलोमीटर लंबी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सात लाख सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से कई पर विचार किया गया और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया गया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा 'नरक चतुर्दशी' पर अपना घोषणा पत्र क्यों ला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पौराणिक कथाओं और इतिहास की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर की कैद से महिलाओं को मुक्त कराया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने सभी वादों को लागू कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है।

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 17 नवंबर को होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें गेहूं के लिए 2,700 रुपये प्रति क्विंटल एवं धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसएपी) 3,100 रुपये प्रति क्विंटल, और 'लाड़ली बहना योजना' की लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। गरीब परिवारों की लड़कियों को स्नातकोत्तर (पीजी) तक मुफ्त शिक्षा, 12वीं कक्षा तक गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा और लाड़ली बहना तथा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनाओं की लाभार्थियों के लिए 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना घोषणा पत्र के मुख्य आकर्षण हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी के प्रदेश प्रमुख वीडी शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेताओं ने 96 पृष्ठों का यह संकल्प पत्र यहां जारी किया।अपने संकल्प पत्र में, भाजपा ने गेहूं और धान के लिए प्रति क्विंटल क्रमशः 2,700 रुपये एवं 3,100 रुपये की एमएसपी का वादा किया है। लाड़ली बहना योजना की लाभार्थियों के लिए आवास और प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी या स्वरोजगार के अवसर का भी वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र के अनुसार, यदि भाजपा सत्ता में बनी रहती है तो पार्टी राज्य में आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थान और एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) जैसे चिकित्सा संस्थान स्थापित करेगी। घोषणा पत्र में छह नए एक्सप्रेसवे और आदिवासी समुदाय के सशक्तिकरण के लिए तीन लाख करोड़ रुपये के बजट का भी वादा किया गया है। इस अवसर पर, नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने घोषणा पत्र को सरकार का 'रोडमैप' बनाकर अक्षरशः लागू किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने निगरानी तंत्र के माध्यम से घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर भी नजर रखती है। प्रदेश भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने कहा कि एक समिति ने समाज के सभी वर्गों और बुद्धिजीवियों से चर्चा और सुझाव मांगने के बाद घोषणा पत्र तैयार किया। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में लोगों की आकांक्षाएं शामिल हैं और इस पर चर्चा के लिए मंडल स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी की 11,000 किलोमीटर लंबी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सात लाख सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से कई पर विचार किया गया और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया गया। चौहान ने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा 'नरक चतुर्दशी' पर अपना घोषणा पत्र क्यों ला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पौराणिक कथाओं और इतिहास की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर की कैद से महिलाओं को मुक्त कराया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने सभी वादों को लागू कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया है।

पांच साल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को बनाया अपराध का गढ़ : राजनाथ

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारक धुंआधार रैली कर रहे हैं।इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने एमसीबी जिले के सलगवां कला में चुनावी रैली की। इस दौरान राजनाथ सिंह के प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने प्रदेश सरकार को घोटालों की सरकार कहा।राजनाथ के मुताबिक कांग्रेसियों को कोयले से काफी प्यार है। केंद्र में जब थी तब सबसे बड़ा कोल स्कैम किया था।वहीं अब राज्य सरकार भी कोल घोटाला कर चुकी है। कोल प्रेम के कारण कांग्रेस अपने हाथों के साथ मुंह भी काला कर लेते हैं।

राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस उम्मीद से जनता ने कांग्रेस सरकार को चुना था,वो उम्मीद और विश्वास टूट गया है।प्रदेश में अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं।अपराधियों की असली जगह जहां होनी चाहिए वहां नहीं है। अपराध के मामले में नंबर एक है। प्रदेश को एटीएम बना दिया गया है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल फंडिंग के लिए करती है।राशन घोटाला, शराब घोटाला, और सबसे पसंदीदा घोटाला कोल घोटाला।जहां इनको कोयला दिखता है वहीं ये अपनी हाथ काले कर लेते हैं।क्योंकि कोयले से कांग्रेस का दोस्ताना है।

केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के मुताबिक केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचने देती।प्रदेश में करीब 18 लाख मकान केंद्र की योजना के तहत बनने थे लेकिन प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की गरीब जनता को घर नहीं मिला।

राजनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है।हत्या,लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं।अनेक परिवार की बेटियां गायब हो गई है।लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा हम करते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कहने की अब जरुरत नहीं।पूरे देश ही नहीं विश्व में भारत का नाम मोदी जी ने ऊंचा किया है। पहले वैश्विक मंचों पर जब भी भारत अपनी कोई बात रखता था तो उसे सुना नहीं जाता था।लेकिन अब समय बदल गया है।मोदी जी की नीतियों के कारण बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों को ना सिर्फ सुना जाता है, बल्कि अमल भी किया जाता है।

मतदान दल के कर्मचारियों ने डाक मतपत्र से किया मतदान

कोरबा। वे अधिकारी-कर्मचारी जिनकी ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु मतदान दलों में लगाई गई है, ऐसे अधिकारियों-कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान किया। प्रशिक्षण स्थल पर बनाए गए डाक मतपत्र मतदान सुविधा केंद्र में मतदान की व्यवस्था होने पर मतदान दल में शामिल मतदाताओं ने उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका अदा की। डाक मतपत्र से मतदान करने वाली मतदान कर्मी श्रीमती ममता डहरिया ने बताया कि उनकी ड्यूटी मतदान दलों में लगाई गई है। इसलिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चयन करने के साथ ही आज प्रशिक्षण स्थल में मतदान किया है। मतदान कर्मी श्री पंकज जोशी और पंचराम साहू ने बताया कि मतदान दल में ड्यूटी लगने के पश्चात् आज उन्होंने भी प्रशिक्षण स्थल में अपना महत्वपूर्ण वोट डाक मतपत्र के माध्यम से किया है।

महापौर यादव मिले मुख्यमंत्री से, वायरल ऑडियो को बताया असत्य और भ्रामक

- **सीएम ने कहा कांग्रेस के लिए करते रहो प्रचार, प्राथमिक सदस्यता जल्द होगी बहाल**

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कल दोपहर को बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद यादव तत्काल राजधानी रायपुर पहुंचे और शुक्रवार की देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी के साथ हुई बातचीत के वायरल ऑडियो को असत्य और भ्रामक होने की जानकारी दी, इसके बाद मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि वे विधानसभा चुनाव में बिलासपुर संभाग से लड़े रहे कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार-प्रसार करें, उनकी सदस्यता जल्द ही बहाल कर दी जाएगी।

उल्लेखनीय हैं कि पूर्व कांग्रेस विधायक और बिलासपुर के निर्दलीय प्रत्याशी अरुण तिवारी के साथ टेलीफोन पर बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव की हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को महापौर यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। निलंबन आदेश आने के बाद यादव रायपुर रवाना हुए और शुक्रवार की देर शाम उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। यादव ने मुख्यमंत्री से कहा कि ऑडियो में प्रचारित बातें असत्य और भ्रामक हैं, वे विगत 40 वर्षों से कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी बात सहानुभूति पूर्वक सुनी है और कहा कि निलंबन का मतलब निष्कासन नहीं है। तुम अभी भी कांग्रेस के सिपाही हो और अपना पक्ष पार्टी की अनुशासन समिति के सामने रखो, वह इस पर विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने उनसे कांग्रेस का प्रचार करने और प्रत्याशियों को जिताने में मदद करने के लिए भी कहा। यादव ने मुख्यमंत्री का आभार माना और अपने समर्थकों तथा नागरिकों से अपील की कि वे बिलासपुर जिले की सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को दिलाएं। यादव ने कहा कि भैया मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार जिले में कांग्रेस का प्रचार करेंगे।

नक्सल प्रभावित बस्तर में मतदान कर्मियों को पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने 404 उड़ानें भरीं

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण 7 नवंबर को संपन्न हुआ। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा कि भारतीय वायु सेना ने 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में नक्सल प्रभावित बस्तर डिवीजन में वोटिंग मशीनों के साथ मतदान दलों को ले जाने के लिए छह दिनों के लिए आठ एमआई -17 हेलिकॉप्टरों के साथ 404 उड़ानें भरीं। राज्य के 20 विधानसभा क्षेत्रों में बस्तर संभाग के 12 निर्वाचन क्षेत्र शामिल थे, जहां पहले चरण में 78 प्रतिशत मतदान हुआ था।

छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया। उसमें लिखा सभी चुनौतियों को पार करते हुए, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने आठ एमआई 17 के साथ 404 उड़ानें भरीं, 853 मतदान दल के सदस्यों को 43

स्थानों से सुरक्षित रूप से पहुंचाया, जिससे कठिन वामपंथी प्रभावित क्षेत्र में एक सफल चुनावी प्रक्रिया संभव हो सकी। भारत वायु सेना को सलाम।

पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि 7 नवंबर को मतदान के लिए 4 से 6 नवंबर तक 860 से अधिक मतदान दल के सदस्यों को एमआई-17 हेलीकॉप्टरों के माध्यम से बस्तर संभाग के पांच जिलों - सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के 156 मतदान केंद्रों पर भेजा गया। मतदान के बाद अगले तीन दिनों तक सभी पीठासीन अधिकारियों और मतदान दलों के सदस्यों को ईवीएम के साथ संबंधित जिला मुख्यालय ले जाया गया। अधिकारी ने बताया कि अभ्यास 9 नवंबर की शाम तक पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि कार्य योजना के अनुसार, स्थानीय प्रशासन या पुलिस या सुरक्षा बलों ने मतदान कर्मियों को मतदान के दौरान नजदीकी सुरक्षा शिविरों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर ठहराने की व्यवस्था की थी। आईजी ने चुनावों के सुचारू संचालन में योगदान देने के लिए 6 दिनों के लंबे प्रयास के लिए वायु सेना के प्रति आभार व्यक्त किया।

पिछले दिनों क्षेत्र के बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में हेलीकॉप्टरों पर नक्सली गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं। 2008 के विधानसभा चुनावों में, बीजापुर के पीडिया गांव से वोटिंग मशीनों और कर्मियों के साथ उड़ान भरने के तुरंत बाद नक्सलियों ने भारतीय वायुसेना के हेलिकॉप्टर पर गोलीबारी की। हमले में फ्लाइट इंजीनियर सार्जेंट मुस्तफा अली की कॉकपिट में मौत हो गई। विमान के कप्तान, स्क्वाड्रन लीडर टी.के. चौधरी, गोलियों से हेलिकॉप्टर के रोटरक्राफ्ट को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उड़ान भरने में कामयाब रहे और जगदलपुर में उतरे।

कोरबा से गेवरा रोड के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाया

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों के बेहतर, सुविधाजनक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के साथ-साथ क्षमता में वृद्धि के लिए आधुनिक एवं उन्नत तकनीक को अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली यानी ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग सिस्टम में दो स्टेशनों के निश्चित दूरी पर सिग्नल लगाए जाते हैं। नई व्यवस्था में स्टेशन यार्ड के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से आगे लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर पर सिग्नल लगाए गए हैं। जिसके फलस्वरूप सिग्नल के सहारे ट्रेनें एक-दूसरे के पीछे चलती रहती है। अगर किसी कारण से आगे वाले सिग्नल में तकनीकी खामी आती है तो पीछे चल रही ट्रेनों को भी सूचना मिल जाएगी। जो ट्रेन जहां रहेंगी और वो जहां है वहीं रुक जाएंगी।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बिलासपुर से दाधापारा, बिल्हा, गतौरा, जयरामनगर, लटिया, अकलतरा, उसलापुर, घुटकू, चांपा से गेवरा रोड , नागपुर से भिलाई के साथ कुल 383 किलो मीटर सेक्शन ऑटोमैटिक सिग्नल प्रणाली से लैस है। कोरबा से गेवरा रोड के कार्य पूरे होने से चांपा से गेवरा रोड तक का पूरा सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग से लैस हो गया। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम के लागू हो जाने से एक ब्लॉक सेक्शन में एक ही रूट

पर एक से अधिक ट्रेनें चल सकती है। इससे रेल लाइनों पर ट्रेनों की रफ्तार के साथ ही संख्या भी बढ़ गई है। वहीं, कहीं भी खड़ी ट्रेन को निकलने के लिए आगे चल रही ट्रेन के अगले स्टेशन तक पहुंचने का भी इंतजार नहीं करना पड़ता है। स्टेशन यार्ड से ट्रेन के आगे बढ़ते ही ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, यानि कि एक ब्लॉक सेक्शन में एक के पीछे दूसरी ट्रेन आसानी से चलती है। इसके साथ ही ट्रेनों के लोकेशन की जानकारी मिलती रहती है।

इस कड़ी मे नागपुर से भिलाई 279 किलोमीटर, बिलासपुर-अकलतरा के मध्य 27 कि.मी., बिलासपुर-बिल्हा के मध्य 16 कि.मी. एवं बिलासपुर-घुटकू के मध्य 16 कि.मी., चांपा से गेवरा रोड 45 किलोमीटर जैसे रेल खंडो में आटोमेटिक सिग्नल प्रणाली लागू की गई है। साथ ही कई महत्वपूर्ण रेलखंडों में इस प्रणाली को स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली लागू हो जाने से बहुआयामी लाभ रहा है।

80 साल से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से किया मतदान

कोरबा। कोरबा में जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार और स्वीप नोडल अधिकारी विश्वदीप के निर्देशन मे मतदाता जागरूकता अभियान चल रहा है। लोगों को टीम द्वारा अपने वोट का महत्व समझाते हुए मतदान करने की अपील की जा रही है7 जिससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। इस बार विधानसभा निर्वाचन में शत प्रतिशत मतदान होने की संभावना है। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग द्वारा इस वर्ष 80 वर्ष के अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं जिनको मतदान केन्द्रों तक जाने में दिक्कत है, उनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। इस सुविधा में सेक्टर अधिकारी की देखरेख में पीठासीन अधिकारी अपने दल के साथ बीएलओ के माध्यम से पूर्व में आवेदन किये गए 80 प्लस व दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर डाक मतपत्र के माध्यम से उन्हें वोट डालवा रहे हैं, जो की परिणाम के दिन गिनती की जाएगी। यह सुविधा कोरबा जिले की चारों विधानसभाओं में भी उपलब्ध कराई गई है। कोरबा विधानसभा के रूट क्रमांक चार कोसबाड़ी, खरामोरा, डिंगापुर में आज 92 वर्ष की वृद्धा श्रीमती फुलकुंवर निवासी खरामोरा ने घर में ही पूरी पारदर्शिता के साथ अपना वोट डाक मतपत्र के जरिए डाला है। यह सुविधा पहली बार पाकर फुलकुंवर ने खुशी जाहिर करते हुए धन्यवाद दिया है। इसी प्रकार कोसबाड़ी निवाशी शकुंतला और नीम चौक बस्ती निवासी शीतलमती 90 वर्ष ने भी साथ वोट दी है। सेक्टर अधिकारी ने बताया की रूट में कुल 17 ऐसे मतदाता हैं जो पूर्व में आदेवन किया है आज उनके घर जाकर मतदान कराया गया है। स्वीप टीम प्रभारी अनिल रात्रे ने बताया की निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में स्वीप कार्यक्रम लगातार चल रहा है जिससे लोग अपने वोट डालने के प्रति जागृत हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सैकड़ो महिलाओं ने ली भाजपा की सदस्यता

कोरबा। बेमइ बसाहट क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। ठीक विधानसभा चुनाव के बीच ली गई भाजपा की सदस्यता से कांग्रेसजनों में हड़कम्प मच गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कोरबा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी लखनलाल देवांगन सीएसईबी क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए पहुंचे थे। वह कॉलोनी के निवासियों से समर्थन की अपील कर रहे थे। जनसम्पर्क के दरम्यान लखनलाल देवांगन के महापौर रहते हुए बेमइ सहित कोरबा में किए गए विकास कार्यों से प्रभावित सैकड़ो महिलाओं ने भाजपा की रीति नीति पर निष्ठा व्यक्त करते हुए भाजपा में प्रवेश ले लिया। भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाली सभी महिलाओं का स्वागत करते हुए उन्हें सम्बोधित भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक के लिए सोचती और काम करती है। इसी वजह से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में आज देश तेजी के साथ विकास कर रहा है।

आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस प्रत्याशी को नोटिस

बिलासपुर। विधानसभा चुनाव के लिए लागू आचरण संहिता के उल्लंघन के मामले में बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पाण्डेय को नोटिस जारी किया गया है। रिटर्निंग अफसर सुभाष सिंह राज ने शैलेश से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है। रिटर्निग अफसर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है। प्राप्त शिकायत पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पाण्डे ने विधानसभा क्षेत्र के मंदिर चौक से सिंधी कालोनी रोड, भक्त कंवर राम रोड, मुख्य मार्ग एवं अयोध्या नगर (चर्च गली), डॉ। घाटगे नर्सिग होम, सिंधी कालोनी बिलासपुर में बिजली के खंभों में बैनर पोस्टर लगाया है। मेन रोड पर बैनर पोस्टर से प्रवेश द्वार भी बनाया गया है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन है। आयुक्त नगर निगम बिलासपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त शिकायत की पुष्टि भी हो रही है। उनका यह कृत्य आदर्श आचार संहिता एवं छग संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 का उल्लंघन है।

छठ पूजा स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा 15 व 16 को

बिलासपुर। छठ पूजा के दौरान ट्रेन में होने वाली अतिरिक्त भीड़-भाड़ के दौरान यात्रियों को अधिक से अधिक कन्फर्म बर्थ/सीट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दुर्ग एवं पटना के मध्य एक फेरे के लिए छठ स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन व्हाया राउरकेला, रांची, गया के मार्ग से चलाई जा रही है। यह ट्रेन 08793 नंबर के साथ दुर्ग से 15 नवंबर को दोपहर 14.45 बजे दुर्ग से प्रस्थान करेगी। इस ट्रेन का रायपुर आगमन 15.40 बजे एवं प्रस्थान 15.45 बजे, भाटापारा आगमन 16.27 बजे एवं प्रस्थान 16.29 बजे, बिलासपुर आगमन 17.35 बजे एवं प्रस्थान 17.44 बजे, चाम्पा आगमन 18.23 बजे एवं प्रस्थान 18.25 बजे, रायगढ़ आगमन 19.18 बजे एवं प्रस्थान 19.20 बजे, झारसुगुड़ा आगमन 20.40 बजे एवं प्रस्थान 20.42 बजे तथा यह ट्रेन राउरकेला, हटिया, रांची, मुरी, बोकारो, चंद्रपुरा, गोमो, कोडरमा, गया, जहानाबाद स्टेशन होते हुए अगले दिन 16/11/2023 को सुबह 09.30 बजे पटना पहुँचेगी। इसी प्रकार यह ट्रेन 08794 नंबर के साथ 16 नवंबर (गुरुवार) को प्रात: 10.30 बजे पटना स्टेशन से दुर्ग के लिए प्रस्थान करेगी।

रामानुजगंज के बच्चों ने रैली निकाल की मतदान की अपील

रामानुजगंज। 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें इसके लिए चुनाव आयोग लगातार अपनी कोशिशों में जुटा है। आयोग ने अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया है। रामानुजगंज में बच्चों ने रैली निकालकर वोटरों को जागरुक किया और आग्रह किया कि वो विकास के लिए अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आप वोट नहीं भी डालना चाहते हैं तो नोटा के बटन का इस्तेमाल करें जिससे चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को भी ये पता चले की कितनी संख्या में लोग नेताओं से नाराज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग लगातार इस कोशिश में है कि दूसरे चरण के मतदान में वोटर बड़ी संख्या में घर से बाहर निकले और मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना कीमती वोट डाले। वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग बैनर पोस्टरों का तो सहारा ले ही रहा है। आयोग अब बच्चों के माध्यम से भी लोगों के बीच वोट को लेकर जागरुकता फैलाने की कोशिशों में जुटा है।

नक्सलियों ने ली भाजपा नेता दुबे की हत्या की जिम्मेदारी

नारायणपुर। भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली है। भाकपा माओवादी पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी ने पर्चा जारी कर बीजेपी नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली। नक्सलियों ने पर्चे में लिखा है कि रतन दुबे को जनविरोधी नीतियों पर अमल करने के कारण मौत की सजा दी गई हैं। नक्सलियों ने नारायणपुर की आमदई लौह खदान निको जायसवाल कंपनी में काम कर रहे स्थानीय कर्मचारियों को तुरंत काम बंद करने की भी अपील की है। बीते 4 नवंबर को चुनाव प्रचार के दौरान नक्सलियों ने भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या कर दी थी। नक्सलियों ने कौशलनार बाजार में प्रचार के दौरान भाजपा नेता पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नक्सलियों की इस वारदात का वीडियो भी सामने आया था। नारायणपुर में 7 नवंबर को चुनाव से तीन दिन पहले नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। भाजपा नेता की हत्या के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया।

कांग्रेस के लिए क्यों कठिन हुई सरगुजा की डगर

सरगुजा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के बाद यदि किसी जगह पर दलों का फोकस होता है तो सरगुजा है।सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें आती हैं।इस समय ये 14 सीटें कांग्रेस के पास है।पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 90 में से 68 सीटों पर जीत हासिल करते हुए 15 साल से सत्ता में जमी बीजेपी को बाहर किया था। उस वक्त बीजेपी विरोधी लहर और टीएस सिंहदेव के घोषणापत्र में की गई मेहनत के साथ किसान कर्जमाफी के वादे ने कांग्रेस के लिए तुरूप के इक्के का काम किया।लेकिन क्या अब सरगुजा पिछले चुनाव का इतिहास दोहराएगा।

सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं। जशपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी)। इन छह जिलों में 14 सीटें, जशपुर जिले में कुनकुरी, पत्थलगांव और जशपुर, सरगुजा जिले में अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर, बलरामपुर में प्रतापपुर, रामानुगंज और सामरी, सूरजपुर में

प्रेमनगर और भटगांव, कोरिया में बैकुंठपुर और एमसीबी जिले में मनेंद्रगढ़ और भरतपुर-सोनहत हैं।जिनमें 17 नवंबर को मतदान होने हैं।इन 14 सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।वहीं 5 सीटें सामान्य हैं।

14 में से 14 सीटें जीतने के बाद भूपेश सरकार में तीन मंत्री सरगुजा संभाग से बने।जिसमें टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत और प्रेमसाय सिंह टेकाम थे।लेकिन चुनाव से पहले ही ना सिर्फ प्रेमसाय सिंह टेकाम का मंत्री पद छीना गया।बल्कि मौजूदा चुनाव में उन्हें प्रतापपुर से टिकट भी नसीब नहीं हुई है। इसी के साथ चिंतामणि महाराज (सामरी), बृहस्पत सिंह (रामानुगंज) और विनय जायसवाल (मनेंद्रगढ़) का टिकट भी कटा है।

सरगुजा संभाग में 4 मौजूदा विधायकों के टिकट कटे।जिनमें से बृहस्पत सिंह को लेकर पहले ही टीएस सिंहदेव ने नाराजगी जाहिर की थी। बाकी के तीन विधायकों का टिकट सर्वे के आधार पर काटा गया।इस मामले में टीएस सिंहदेव का भी मानना है कि दूसरे चरण के चुनाव में कांग्रेस को कुछ झटके जरुर लगेंगे।लेकिन बृहस्पत को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि उन्होंने अपनी लाइन क्रास कर दी थी।इसके बाद भी टीएस सिंहदेव ने कहा कि यदि सर्वे में बृहस्पत सिंह जीत रहे होते,तो मैं रास्ते में नहीं खड़ा होता।लेकिन सर्वे में उनके खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश दिखा।

सरगुजा संभाग में पिछली बार लोगों ने ये सोचकर वोटिंग की थी कि उन्हें पहली बार संभाग से सीएम मिलने वाला है। टीएस सिंहदेव सीएम की रेस में सबसे आगे थे।उनकी मेहनत हर ओर दिखी भी थी।टीएस सिंहदेव की स्वीकार्यता को लेकर ही संभाग के वोटर्स ने बिना किसी आशंका के हर उस कैंडिडेट को जीताया जिसके लिए टीएस सिंहदेव ने वोट मांगे।लेकिन रिजल्ट के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच आलाकमान ने भूपेश बघेल को चुना।उस दिन से लेकर मौजूदा चुनाव तक भूपेश बघेल को लेकर ही कांग्रेस माहौल बना रही है।जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब सरगुजा में बन सकता है। क्योंकि जब भूपेश बघेल सीएम बने और टीएस सिंहदेव से उनकी दूरियां बढ़ी तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान सरगुजा का ही हुआ।इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार सरगुजा की डगर कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल जरुर है।

सीतापुर कांग्रेस प्रत्याशी व मंत्री अमरजीत भगत का विरोध, वापस जाओ के लगे नारे

सरगुजा। छत्तीसगढ़ के मंत्री और सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत का विरोध लगातार नजर आ रहा है। चिरगांव के बाद ग्राम पंचायत वंदना में भी अमरजीत भगत के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दिया। लोगों ने वापस जाओ और गुंडागर्दी नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जैसे जैसे पास आ रहा है राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। कांग्रेस बीजेपी व अन्य दल

के प्रत्याशी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं लोगों से जनसंपर्क कर जीत की अपील कर रहे हैं। सरगुजा के 14 विधानसभा सीटों में भी दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान है। भाजपा सरगुजा में जहां बड़े बड़े मंत्रियों को उतार रही है तो कांग्रेस भी जीत को लेकर ताल ठोंक रही हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए इस बार सरगुजा की राह आसान नहीं दिख रही है। सीतापुर से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी अमरजीत भगत शुक्रवार को ग्राम पंचायत वंदना में प्रचार करने पहुंचे थे। मंत्री के वहां पहुंचते ही ग्रामीण अमरजीत भगत यहां से वापस जाओ, गुंडा गर्दी नहीं चलेगी के नारे लगाते दिखे। जिसके बाद मंत्री वहां से निकल गए। इससे पहले चिरगांव प्लांट को लेकर भी महिलाओं ने मंत्री को काले झंडे दिखाए थे। कांग्रेस ने मंत्री अमरजीत भगत को फिर से मैदान में उतारा है तो भाजपा ने रिटायर्ड बीएसएफ जवान राम कुमार टोप्पो को टिकट दिया है।

संक्षिप्त समाचार

कांग्रेस प्रत्याशी के काफिले पर पथराव करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। बेमेतरा में 8 नवंबर की रात्रि करीबन 09.45 बजे राज्य के पीएचई मंत्री व नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवागढ़ थाने से मिली जानकारी अनुसार 8 नवंबर की रात को गुरु रुद्र कुमार ग्राम झाल से नवागढ़ वापस आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गुरु रुद्रकुमार के काफिले पर पथराव किया गया। इसे लेकर थाना में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 336, 427, 34 कायम कर विवेचना में लिया गया। ग्रामीणों एवं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही आरोपी टेकराम साहू उम्र 30 वर्ष ग्राम झाल, धर्मेन्द्र विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष, ग्राम झाल, थाना नवागढ़, लोमेश विश्वकर्मा उम्र 30 वर्ष ग्राम झाल, थाना नवागढ़ जिला बेमेतरा से पूछताछ करने पर ज्ञात हूआ कि गांव में गुरु रूद्रकुमार के कार्यक्रम में अपनी मांगों को लेकर बहस हुई थी। उसके बाद कार्यक्रम छोड़कर तीनों ठाकुर देव चौक के पास आ गए और अंधेरे में बैठकर शराब पीने लगे। कुछ देर बाद जब गुरु रुद्र कुमार की काफिला वहां से गुजर रहा था तब शराब के नशे में इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तीनों आरोपी को 10 नवंबर को गिरफ्तार कर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। किया गया है। मामले की जांच जारी है।

विशेष टिकट चेकिंग अभियान, रायपुर मंडल को 107320 का राजस्व प्राप्त

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिससे यात्रियों को टिकट लेने के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है, साथ ही यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि वे उचित टिकट लेकर सही कोच में बैठे एवं अपनी सुखद यात्रा करें। यात्रियों को टिकट लेकर यात्रा करने हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से आज 10 नवम्बर को स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के ट्रेनों मे रेलवे मजिस्ट्रेट श्री ग्रिजेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में सहायक वाणिज्य मंडल प्रबंधक श्री दुलार साय चौहान, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक श्री टाटा बाबु राव एवं मंडल मुख्य टिकट निरीक्षक श्री ए.जेना सहित 11 टिकट चेकिंग स्टाफ, 07 आरपीएफ स्टाफ एवं 07 जीआरपी स्टाफ भी शामिल थे। इसमें साउथ बिहार एक्सप्रेस एवं आजाद हिन्द एक्सप्रेस में चेकिंग की गई। इस मजिस्ट्रेट टिकट चेकिंग अभियान में कुल 209 मामलों से 107320 रुपये बतौर जुर्माना वसूला गया।

आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए पालक कर रहे हैं लाटरी खुलने का इंतजार

रायपुर। राजधानी रायपुर में शुरू होने वाले पांच स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश को लेकर बच्चों के साथ ही पालकों को भी काफी बेसब्री से इंतजार हैं क्योंकि अभी तक लॉटरी नहीं निकाली गई हैं। प्राइमरी की कक्षाओं में सीट से कई गुना आवेदन मिले हैं। वहीं दसवीं-12वीं में प्रवेश के लिए छात्र ज्यादा उत्साहित नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक पांच स्कूलों के लिए 14 अक्टूबर तक आवेदन लेना था। 15 को लाटरी निकालकर 16 से छात्रों को प्रवेश देना था लेकिन अभी तक प्रवेश से संबंधी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इन स्कूलों में बच्चों को सीट मिल जाए यह सोचकर कई पालकों ने अपने बच्चों के आनलाइन-आफलाइन दोनों तरह से मोबाइल नंबर बदलकर कई फार्म भरे हैं। इन आवेदनों में बच्चे का नाम और उनके स्वजन का नाम तो एक ही है, लेकिन मोबाइल नंबर अलग-अलग हैं। बच्चों के स्वजन रोजाना स्कूल जाकर प्रवेश के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। भनपुरी स्थित काशीराम शर्मा शासकीय स्कूल में पहली से 12वीं तक पढ़ाई होगी। सभी में 50-50 सीटें हैं। यहां 2,200 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। सबसे ज्यादा आवेदन प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए मिले हैं। अभी यहां हिंदी में पढ़ाई हो रही है। इंग्लिश मीडियम के लिए एडमिशन होने पर दो पालियों में कक्षाएं लगाई जा सकती है। गुढियारी स्थित शशिबाला गर्ल्स स्कूल में अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम की पढ़ाई होगी। पहली से 12वीं की कक्षाएं शुरू करने के निर्देश मिले हैं। लेकिन यहां सभी कक्षाओं के लिए बैठक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

बस्तर में मतदान कर्मियों को लाने-ले जाने के लिए आठ हेलिकॉप्टरों ने भरीं 404 उड़ानें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में मतदान दलों को तैनात करने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारतीय वायु सेना के आठ एमआई—17 हेलीकॉप्टरों ने छह दिनों में 404 उड़ानें भरीं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के मुताबिक, बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार की घोषणा और कुछ नक्सली घटनाओं को छोड़कर आमतौर मतदान शांतिपूर्ण रहा, जिसमें वायुसेना ने बड़ी भूमिका निभाई।

बस्तर संभाग के 12 विधानसभा क्षेत्रों समेत 20 सीटों पर सात नवंबर को मतदान हुआ। अन्य 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 78 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को एक्स पर बताया, सभी चुनौतियों को पार करते हुए, भारतीय वायु सेना ने आठ एमआई 17 के साथ 404 उड़ानें भरी, 853 मतदान दल के सदस्यों को 43 स्थानों से सुरक्षित रूप से पहुंचाया, जिससे कठिन वामपंथी प्रभावित क्षेत्र में एक सफल चुनावी प्रक्रिया संभव हो सकी। भारतीय वायु सेना को सलाम।बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि सात नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान के लिए चार से छह नवंबर तक बस्तर संभाग के पांच जिलों सुकमा, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के 156 मतदान केंद्रों के लिए 860 से अधिक मतदान दल के सदस्यों को एमआई-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजा गया था। सुंदरराज ने बताया कि मतदान समाप्त होने के बाद क्रमबद्ध तरीके से अगले तीन दिनों में सभी पीठासीन अधिकारियों, ईव्हीएम मशीन तथामतदान दल के सभी सदस्यों को संबंधित जिला मुख्यालय वापस लाया गया।

यह प्रक्रिया नौ नवंबर को संपन्न हो गई। उन्होंने बताया कि मतदान कर्मियों को ठहराने के लिए संबंधित सुरक्षा शिविर और अन्य उचित स्थानों में सुरक्षित व्यवस्था प्रशासन, पुलिस और सुरक्षाबलों के अधिकारियों ने की थी। पुलिस महानिरीक्षक ने शांतिपूर्ण मतदान को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारतीय वायुसेना के प्रति आभार व्यक्त किया है। नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में पूर्व में हेलीकॉप्टरों पर नक्सली गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं।

70 सीटों में मतदान का समय भी रहेगा अलग-अलग

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में 17 नवम्बर को 70 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे. इसके लिए सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. केवल बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नौ मतदान केंद्रों कामरभौदी, आमामोरा, ओढ, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, सहबीनकछार और कोदोमाली में सवेरे सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा. इनके अलावा बिन्द्रानवागढ़ के शेष मतदान केंद्रों में अन्य 69 विधानसभा क्षेत्रों की तरह सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक वोट डाले जाएंगे.राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में मतदान वाले 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं. दूसरे चरण में राज्य के कुल एक करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इनमें 81 लाख 41 हजार 624 पुरुष मतदाता, 81 लाख 72 हजार 171 महिला मतदाता तथा 684 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं.विधानसभा आम निर्वाचन के लिए दूसरे चरण में भरतपुर-सोनहट, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी-बालोद, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे.

निगरानी दलों ने 66.88 करोड़ की नगदी और वस्तुएं की जब्त

रायपुर। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 9 नवम्बर तक की स्थिति में 66 करोड़ 88 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 18 करोड़ 13 लाख रुपए की नगद राशि शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 9 नवम्बर तक 47 हजार 846 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत एक करोड़ 37 लाख रुपए है। साथ ही 4 करोड़ 7 लाख रुपए कीमत की अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। सघन जाँच अभियान के दौरान 20 करोड़ 57 लाख रुपए कीमत के 493 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत 22 करोड़ 74 लाख रुपए है, भी जब्त की गई हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।

महासमुंद के बेमचा मैदान में मोदी की आमसभा 13 को

मुंगेली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन, यानी सोमवार, 13 नवंबर को बेमचा मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए आने वाले है, जिसकी तैयारी में भाजपा कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। क्योंकि श्री मोदी मुंगेली में आमसभा को संबोधित करने के बाद सीधे बेमचा पहुंच रहे हैं।

रायपुर भाजपा कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार श्री मोदी 13 नवंबर को सुबह राजधानी रायपुर पहुंचेंगे जहां से वे सीधे मुंगेली के लिए रवाना हो जाएंगे, वहां 11 बजे आमसभा को संबोधित करने के बाद 12.30 बजे महासमुंद पहुंचे जहां से वे बेमचा मैदान के लिए रवाना होंगे और वहां चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद अगले पड़ाव के लिए रवाना हो जाएंगे। इसकी अधिकृत प्रोटोकाल 12 नंवबर को जारी किया जाएगा। बेमचा में होने वाले मोदी की जनसभा में 8 विधानसभा के करीब 75 हजार लोग शामिल होंगे। आमसभा को भव्य बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। महासमुंद जिलाध्यक्ष रूपकुमारी चौधरी ने बताया कि जिले के सरायपाली, खल्लारी और महासमुंद के अलावा रायपुर जिले के आरंग और गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा से और कार्यकर्ता मोदी की आमसभा में पहुंचेंगे। इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। बिलासपुर संभाग क्षेत्र के मुंगेली विधानसभा में मोदी 13 नवंबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली सुबह 11 बजे बछेरा (जमकुही) बायपास रोड के पास मे होने जा रही है। प्रधानमंत्री के आम सभा में मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, बिल्हा, और नवागढ़ के भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। मुंगेली विधानसभा से पुन्नूलाल मोहले, लोरमी विधानसभा से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, तखतपुर विधानसभा से धर्मजीत सिंह, बिल्हा विधानसभा से धरमलाल कौशिक, और नवागढ़ विधानसभा से दयालदास बघेल चुनावी मैदान में हैं।

महिलाओं के साथ वादाखिलाफी कांग्रेस का चरित्र: डॉ. रमन

रायपुर। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भाजपा की सुनिश्चित जीत को देखते हुए कांग्रेस के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी जी की गारंटियों ने कांग्रेस का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। इनके राष्ट्रीय नेता राहुल और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ की जनता को जो गारंटियां दे गए थे, उन गारंटियों को कांग्रेस ने बार-बार बदलकर यह साबित कर दिया है कि उसे अपने राष्ट्रीय नेताओं पर भरोसा नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री, उनकी सरकार और कांग्रेस पर भरोसा नहीं है। इसलिए अब कांग्रेस अपनी घोषणाओं पर चर्चा करने के बजाय भाजपा के घोषणा पत्र की समीक्षा करने पर ज्यादा जोर दे रही है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि महिला विरोधी कांग्रेस अपनी सरकार का दुरुपयोग करते हुए पुलिस और प्रशासन तंत्र के साथ अपने कार्यकर्ताओं के जरिये हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करा रही है ताकि हमने महिलाओं के हित में जो गारंटी देश के प्रधानमंत्री की ओर से दी है वह महिलाओं तक न पहुंच पाए। महतारी वंदन के फार्म भरवाने हमारे कार्यकर्ता प्रदेश की माताओं, बहनों तक जा रहे है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी उन्हें रोक रहे है। कांग्रेस ने तो महिलाओं को तो कुछ नहीं दिया सिर्फ धोखा दिया। भाजपा महतारी वंदन करने निकली है तो वह भी कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं है। हमे हमारे संकल्प पत्र का प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग सरेआम हो रहा है। भिलाई, वैशाली नगर, दुर्ग, सीतापुर दल्लीराजहरा इलाकों में ज्यादा मिल रहे हैं भाजपा इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग में करेगी। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की वादाखिलाफियों से छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह वाकिफ है। ये वादा तो कर लेते है लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो साफ मुकर जाते है। इसी तरह महिलाओं को प्रियंका गांधी गारंटी दे गई कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे लेकिन कांग्रेस ने इसे बदल कर घोषणा की है कि गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देंगे।भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि महिलाओं से शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया। महिलाओं से वादा किया गया था कि साल में 4 गैस सिलेंडर मुफ्त में देंगे, महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ करेंगे, विधवा पेंशन देंगे, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन देंगे, हर थाने में महिलाओं की सहायता के लिए डेस्क का वादा किया गया था महिलाओं पर होने वाले अपराधों की संख्या पांच साल में इस तरह बढ़ी है कि कोई भी महिला स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। कांग्रेस ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है। एक भी वादा कांग्रेस की सरकार ने नहीं निभाया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि अब तक कांग्रेस 19 बार घोषणाएं कर चुकी है और इन्हें बदलती जा रही है।

सीट भूपेश तय कर लें, हरा कर दिखाऊंगा: बृजमोहन

रायपुर। वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आज पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जोरदार हमला बोलते हुए उनको आरोपों के कठघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाले आर्थिक अपराधियों के वे हिस्सेदार हैं। ईडी की टिप्पणी भी यही इशारा करती है।

बृजमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि बृजमोहन ने हार से बचने के लिए यह नाटक किया है तो मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देता हूं कि स्थान वे तय कर ले, जहां से वे चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूं । उन्होंने कहा बृजमोहन सत्ता के अहंकार में नहीं, लोगों के दिलों में जीता है।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुझ पर जनसंपर्क के दौरान महापौर के निर्वाचन क्षेत्र अब्दुल रऊफ वार्ड में पठान ड्रेस पहने लोगों ने हमला किया। मेरे सुरक्षा कर्मियों ने मुझे पीछे खींच लिया तो बड़ी दुर्घटना नहीं हो पाई। बृजमोहन ने कहा मैं सात बार का विधायक हूं। एक जनप्रतिनिधि हूं। परंतु इस हमले के बाद मुख्यमंत्री की जो प्रतिक्रिया आई वह बेहद हैरान करने वाली गैर जिम्मेदाराना थी। अपराधियों के लिए दो शब्द बोलने की बजाय उन्होंने मुझ पर ही अपशब्दों का प्रयोग कर दिया और अपराधियों को संरक्षण देने खड़े हो गए। भूपेश बघेल का काम ही यही है। वे हर अपराधी की पैरोकारी करने खड़े हो जाते हैं। यह मेरा ही अपमान नहीं, रायपुर की उस जनता का अपमान है जिसने पिछले 35 सालों से मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। मुख्यमंत्री को अपने शब्दों के लिए रायपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वरना मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ को केरल और पश्चिम बंगाल की तरह बनाना चाहते है।

बृजमोहन ने कहा कि मुख्यमंत्री पैसाखोर हो गए हैं। जो उन्हें अपनी काली कमाई का हिस्सा देता है, उसके साथ में हमेशा खड़े नजर आते हैं, उनका बचाव करते नजर आते हैं। इतने आरोप लगने के बाद भी अपने उन टट्टुओं जिन पर जग्गी हत्याकांड के आरोप लगे हैं, उन्हें भरपूर संरक्षण मुख्यमंत्री दे रहे हैं। लगता है अपनी पूरी सत्ता ही उन्हें सौंप दी है। बृजमोहन ने कहा कि आपने कई प्रकार के ठेके का जिक्र सुना होगा परंतु अब कांग्रेस पार्टी चुनाव भी ठेके पर दे रही है। ऐसा ही ठेका रायपुर दक्षिण विधानसभा में दिया गया है। जहां पर जोर जबरदस्ती का खेल खेला जा रहा है। लोगों को 17 तारीख चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी जा रही है। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पंजाब के बहाने भूपेश बघेल का राजभवन पर निशाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राजभवन और भूपेश सरकार के बीच चल रहे टकराव के बीच भूपेश बघेल ने फिर से राजभवन को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार की अपील पर जिस तरह से वहां के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है वो केंद्र के लिए शर्मनाक है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी राज्यपाल के पास 12 बिल जो विकास से जुड़े हैं अटके पड़े हैं। राजभवन उन बिलों को पास नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि वो राज्यपालों के जरिए राज्य सरकार को कंट्रोल करे। लोकतंत्र में फेडरल सिस्टम को इस तरह से रोकना बिल्कुल गलत है। मोदी सरकार लोकतंत्र पर प्रहार कर रही है।

राज्यपाल को निशाने पर लेने के बाद भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर सियासी तंज कसा। बघेल ने कहा कि जिस विष्णुदेव साय को ये लोग बड़ा बनाना चाहते हैं। उस विष्णुदेव साय को भाजपा ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। सीएम ने राजनाथ सिंह के पाटन दौरे पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि पाटन की धरती पर उनका स्वागत है, इस धरती को नमन करना चाहिए। राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। आरक्षण को लेकर पहले ही कई मोर्चों पर बयानबाजी हो चुकी है। पंजाब सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पंजाब सरकार के फैसले सही करार दिया और राज्यपाल को लेकर टिप्पणी की। एक बार फिर से राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। क्योंकि पूर्व में आरक्षण बिल पर राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किया था।

बृजमोहन पर हुए हमले को लेकर तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं सीएम : चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल पर प्रचार के दौरान बैजनाथपारा में हुए हमले को गंभीरता से लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इतने गंभीर मामले में भी तुष्टिकरण की राजनीति की एक बार फिर नजीर पेश की है। बृजमोहन ने स्पष्टतौर पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में महापौर एजाज ढेबर की ओर से सुनियोजित तरीके से हमला कराया गया है।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह हमला पहले चरण के चुनाव का कांग्रेसी एक्जिट पोल है। दावा करते हुए कहा कि पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। इससे बौखलाए कांग्रेसियों ने हिंसा का रास्ता अख्तियार किया है। अग्रवाल को रायपुर दक्षिण में हराना नामुमकिन है तो उन्हें रास्ते से ही हटाने की कोशिश की गई। उन पर प्राण घातक हमले की साजिश रची गई।

चंदेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को अपराध और माफिया का गढ़ बनाने वाली कांग्रेस ने बस्तर में हमारे नेताओं की टारगेट किलिंग का षड्यंत्र रचा। हमारे नेताओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। प्रचार के दौरान हमारे एक नेता को भरे चुनाव में जान से मारा गया और अब कांग्रेसी टारगेट किलिंग का षड्यंत्र रायपुर तक पहुंच गया, इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के दौरान हमारे नेताओं पर हमलों की आशंका पहले से अधिक बढ़ गई है। पुलिस राज्य सरकार के दबाव में कांग्रेस के एजेंट की तरह काम कर रही है। आने वाले समय में हिंसा की और भी घटनाएं हो सकती हैं। कांग्रेस के हिंसक इरादे, उसकी नीयत सामने आ गई है। जब राजधानी रायपुर की पहचान, सात बार के विधायक बृजमोहन पर जानलेवा हमला हो सकता है तो आम कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल पर किए गए हमले का मकसद भाजपा को समर्थन दे रही आम जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं में दहशत पैदा करना है। ताकि पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव को प्रभावित किया जा सके।

भाजपा के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र पर अब छत्तीसगढ़ की जनता देगी जवाब : वर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र ही छत्तीसगढिया विरोधी है। 15 साल रमन सिंह को अवसर मिला था, छत्तीसगढ़ के बहुसंख्यक आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का भला कर सके। भाजपा नेताओं को 15 साल अवसर था कि छत्तीसगढिया संस्कृति और समृद्धि का संरक्षण और संवर्धन करते, लेकिन भाजपाइयों ने स्थानीय छत्तीसगढिया जनता की उपेक्षा ही किया है। उक्त बातें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहीं।

उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में सर्व समाज को आरक्षण देने का काम पूरी ईमानदारी से किया है। 76 प्रतिशत वाले नवीन आरक्षण विधेयक में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसी के साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के लोगों को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की जनगणना के लिए क्वांटीफायबल डाटा आयोग का गठन कर प्रमाणिक आंकड़े जुटाए गए। विधि विभाग से परीक्षण के बाद विधानसभा में 2 दिसंबर 2022 को सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ है जिसमें सभी वर्गों की आबादी के अनुसार निर्णय लिया गया है यह विधेयक यदि कानून का रूप लेता तो हर वर्ग के लोग संतुष्ट होंते। सभी वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोडने़ सामाजिक न्याय के फार्मूले को लागू करने का यह विधेयक भूपेश सरकार ने बनाया है। जिसे विगत 11 महीनों से रोकने का सीधा मतलब छत्तीसगढ़ की तीन चौथाई बहुमत का अपमान करना है, छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ आबादी का अपमान करना है।

वर्मा ने कहा है कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक आबादी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की हकीकत जानने के लिए बेहद आवश्यक है, ताकि बहुसंख्यक आबादी के हक, हित और अधिकारों के लिए बेहतर योजना बन सके।

एक और सांसद की बलि

अजय सेतिया

दो साल की सजा होने पर जब जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 8 (3) के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई थी, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि संसद में अडानी और मोदी के रिश्तों पर बोलने के कारण उनकी सदस्यता ली गई। हालांकि जन प्रतिनिधित्व क़ानून अब तमाशा बन कर रह गया है, क्योंकि सुप्रीमकोर्ट कन्विक्शन पर स्टे लगा कर सांसदों की सदस्यता बहाल करने लगा है। लेकिन टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का मामला दूसरा है, उन्हें किसी अदालत ने नहीं, बल्कि खुद संसद की ओर से सजा दी जा रही है। हालांकि आरोप उनका भी वही है कि उन्हें संसद में अडानी के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है। उनके खिलाफ शिकायत पैसे लेकर सवाल पूछने की थी। ऐसा ही एक मामला 2005 में सामने आया था, जब न्यूज चैनल आज तक ने एक स्टिंग आपरेशन दिखाया था। इस स्टिंग आपरेशन में विपक्षी दलों के 11 सांसदों को लिफाफा लेते दिखाया गया था। लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने स्वयं संज्ञान लेकर सांसद पवन कुमार बंसल की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना दी थी। इस कमेटी ने आजतक को तलब किया था, जिसने कमेटी के सामने पेश होकर कहा कि उसने वीडियो कोबरापोस्ट डॉट कॉम के अनिरुद्ध बहल से 48 लाख रूपए में खरीदे थे। अनिरुद्ध बहल ने कमेटी के सामने पेश होकर कहा कि उन्होंने स्टिंग आपरेशन करने के लिए सांसदों को 11 हजार से लेकर एक लाख रूपए तक दिए गए थे। फिर भी उन सांसदों की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय कर दिया गया। उसी निर्णय के आधार पर लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने बहुमत के आधार पर महुआ मोइत्रा को बर्खास्त करने की सिफारिश कर दी है। अब जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा, उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव रखा जाएगा, जो आसानी से पास भी हो जाएगा, क्योंकि एथिक्स कमेटी की तरह लोकसभा में भी भाजपा का पूर्ण बहुमत हासिल है। विपक्ष के सांसदों ने जैसे संसदीय समिति से वाकआउट किया, वैसे ही लोकसभा से भी करेंगे। वर्ष 2005 में भी जब लोकसभा के दस सांसदों को बर्खास्त किया जा रहा था, तब भी वाकआउट हुआ था। तब मसला यह था कि विपक्ष ने कहा था अपराध के मुकाबले सजा ज्यादा है। अब विपक्ष सजा के ही खिलाफ है, विपक्ष इस मसले को अडानी के साथ तो जोड़ ही रहा है, सवाल यह भी खड़ा होगा कि कैश लेना साबित हुआ है क्या। दर्शन हीरानन्दानी ने अपने हल्फिया बयान में कैश देने की बात नहीं कही है। जहां तक उपहार लेने का सवाल है तो सीताराम येचुरी का यह कहना आधारहीन नहीं है कि कौन सांसद उपहार नहीं लेता। बड़े बड़े उद्योगपति सभी सांसदों को दीपावली, होली के वक्त बेशकीमती उपहार भेजते रहते हैं, कोई सांसद उन उपहारों को वापस नहीं करता। उद्योगपतियों का स्वार्थ सिर्फ इतना होता है कि कल को उनके खिलाफ कुछ हो, तो वे उनके साथ भले ही खड़े न हों, उनके खिलाफ न खड़े हों। सवाल यह भी है कि क्या संसद ने ऐसा नियम बनाया है कि कोई भी सांसद किसी उद्योगपति या बड़े पूंजीपति से उपहार नहीं लेगा। अगर यह नियम नहीं बनाया, तो महुआ मोइत्रा के लिए यह नियम कैसे लागू होगा कि उन्होंने अपने मित्र दर्शन हीरानंदानी से लिपस्टिक या बैग या चश्मा उपहार लिया था। महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी दोनों ने यह दावा किया है कि उनकी घनिष्टता थी। अगर दोनों में मित्रवत घनिष्टता थी, तो उनके रिश्तों को उद्योगपति और सांसद के रिश्तों के नजरिए से कैसे देखा जा सकता है। क्या महुआ मोइत्रा को खुद को सही साबित करने के लिए दर्शन हीरानन्दानी और जय अनंत देहाद्राई से उनका आमना सामना नहीं करवाना चाहिए था? क्योंकि यह नहीं हुआ, इसलिए विपक्ष इसे अडानी के साथ जोड़ेगा। कहेगा कि अडानी की आलोचना के कारण पहले राहुल गांधी को बर्खास्त किया गया, अब महुआ मोइत्रा को किया जा रहा है। सवाल यह है कि देश क्या सोचेगा। जनता में धारणा क्या बनती है? जनता क्या सोचती है? क्या पब्लिक परसेप्शन बनेगा कि भाजपा अपने बहुमत का नाजायज फायदा उठा कर मोदी विरोधी सांसद को बर्खास्त कर रही है। या पब्लिक यह सोचेगी कि महुआ मोइत्रा ने उन वोटरों के साथ धोखा किया, जिन्होंने उन्हें चुना था।

मुद्दा विहीन विधानसभा चुनाव

ललित गर्ग

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां एवं आक्रामकता बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों के चयन, चुनाव जीतने एवं सरकार बनाने को लेकर पूरी आक्रामकता है, लेकिन जनहित के मुद्दों पर गहरा सन्नाटा पसरा है। इन चुनावों में सबसे बड़ी विडम्बना जो हर बार की तरह इस बार भी देखने को मिल रही है, वह है इन चुनावों का मुद्दाविहीन होना और दलबदल की स्थितियों का बढ़चढ़ कर सामने आना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम एवं तेलेगाना में अब मतदाताओं के हाथ में राजनीतिक दलों और नेताओं के भाग्य की कुंजी आ गई है। इन चुनावों में भी हर बार की तरह इस बार भी जातिवादी जुनून, सांप्रदायिक कट्टरता और मतदाता को लुभाने-भरमाने की कोशिशें लोकतन्त्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। चुनाव का समय सिटीजन ग्रुप्स से मिलकर, उनकी समस्याओं को सुनकर, उनके समाधान के लिये तत्पर होने का है, राजनीतिक दल अपनी जनता की मूलभूत समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी लें फिर उन समस्याओं के समाधान का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए जनता से वोट मांगें। देखा जाए तो लोकतंत्र की असली अवधारणा भी यही है। लेकिन मौजूदा समय में धनबल और बाहुबल चुनावों में हावी होता जा रहा है, राजनीति कभी सेवा का जरिया हुआ करती थी किन्तु आज व्यवसाय बनती जा रही है, यह चिंता का विषय है और इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं।

आजादी के अमृतकाल का यह पहला चुनाव है, चुनाव लोकतान्त्रिक प्रणाली के आधार होते हैं। इसी लोकतंत्र के महाकुंभ में लोककल्याण की योजनाओं की चर्चा होती है। राजनैतिक दलों ने चुनावों के अवसर पर लोक कल्याणकारी नीतियां जनता के सामने रखने का प्रचलन शुरू किया जिसे घोषणापत्र कहा गया। हर चुनाव की अलग परिस्थितियां होती हैं अत: घोषणापत्र भी हर बार नये प्रस्तुत किये जाते हैं। लेकिन विडम्बना यह है कि इन घोषणा-पत्रों एवं विजीत दल की सरकार बन जाने के बाद उसकी नीतियों एवं योजनाओं में काफी अन्तर आ जाता है। अत: मतदाता चुनाव के समय जागरूक होकर मतदान करे ताकि उनके साथ किये जाने वाले वायदे यथासंभव पूरे हों। इन

पांच राज्यों के चुनावों में मतदाता को दोहरी भूमिका निभानी होगी- घर के मालिक की भी और घर के पहरेदार की भी। मालिक के नाते उसका कर्तव्य होगा कि वह जनता के हितों के ठेकेदार कहलाने वालों को ठोक बजाकर देखे-परखे। और घर के पहरेदार के नाते उसका कर्तव्य बनता है कि वह सिर्फ जागे ही नहीं बल्कि सतत सावधान भी रहे। इसी जागरूकता और सावधानी का तकाजा है कि वह सत्ता में बैठने के इच्छुक लोगों की कथनी-करनी को विवेक के तराजू पर तोले। चूंकि उसे ही सबसे अधिक खोना और सबसे अधिक पाना है, इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उसी की है। इस जिम्मेदारी को मतदाता वैयक्तिक स्तर पर भी निभाएं- अपने आप से यह पूछकर कि उसके वोट देने का आधार क्या होगा। पहला निर्णय तो मतदाता को यह करना होगा कि उसे वोट देना ही है। फिर यह तय करना होगा कि वह 'गलत' के पक्ष में वोट नहीं देगा। जब प्रत्येक मतदाता अपने वोट का प्रयोग बहुत सोच-समझकर करेगा तभी लोकतंत्र मजबूत होगा और तभी सशक्त भारत का निर्माण हो सकेगा।

राष्ट्र को समग्र दृष्टि से सशक्त एवं विकसित करना, बढ़ती आबादी की बढ़ती मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करना किसी भी लोकतन्त्र में चुनी गई सरकारों का मूल दायित्व होता है। ये चुनी हुई सरकारें जनता की मालिक नहीं होतीं बल्कि उसकी नौकर होती हैं क्योंकि जनता इन्हें केवल पांच साल के लिए ही देश की व्यवस्था चलाने एवं देश की विकास योजनाओं को आकार देने की जिम्मेदारी सौंपती है। इस दौरान चुनी हुई सरकारें अपनी लोक कल्याणकारी नीतियों को चला कर जनता के प्रति मिले दायित्व को पूरा करने का प्रयास करती है। लोकतन्त्र की बहुराजनैतिक प्रणाली में कभी भी विकल्पों की कमी नहीं रहती है, यह भी इस व्यवस्था की खूबसूरती एवं मौलिकता होती है। इसके चलते ही हमने केन्द्र से लेकर विभिन्न राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों की सरकारें देखी हैं। प्रत्येक राजनैतिक दल के अपने कुछ मूलभूत सिद्धान्त होते हैं जिनके तहत वे सत्ता में आने पर लोक कल्याणकारी कदम उठाने का दावा करते हैं। ऐसा ही एक लोककल्याणकारी कदम था भारत में प्रत्येक व्यक्ति को दोनों वक्त भोजन करने का अधिकार देना। भले ही यह कदम डॉ. मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने उठाया, लेकिन इसकी प्रभावी क्रियान्विति 2020 में देश में कोरोना संक्रमण काल के समय मोदी सरकार ने की। तब लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रतिमाह पांच किलो मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई। अब इस योजना को प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने पांच साल और आगे जारी रखने का फैसला किया है। इसका मतलब यह हुआ कि लोक कल्याणकारी नीतियां बनाना हर सरकार का प्राथमिक दायित्व होता है। मोदी सरकार ने ऐसी अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। प्रांतों में राजस्थान में अशोक गहलोत ने तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने भी ऐसी अनेक लोककल्याणकारी योजनाएं चुनाव सन्निकट आते देखकर शुरू की है, जिन्हें हम लोककल्याण से अधिक मुफ्त की रेवड़ियां कह सकते हैं।

मतदाताओं को जागरूक करने के लिये अणुव्रत विश्व भारती एवं भारतीय मतदाता संगठन ने मतदाता जागरूकता अभियान चला रखा है। जिसका उद्देश्य है कि मतदाता को सोचने को विवश करना कि अपराधी हमारा वोट कैसे पा लेते हैं? राष्ट्र की धन-सम्पदा से खिलवाड़ करने वाले भ्रष्टाचारी हमारे आदर्श कैसे बन जाते है? क्यों हम भ्रष्टाचारियों, अवसरवादियों और अपराधियों को वोट देते हैं और फिर वे हम पर राज करते हैं? हम इन स्थितियों को चुपचाप स्वीकार किए रहते हैं। लेकिन आखिर कब तक? कब तक हम ठगे जाते रहेंगे? कब तक मूक दर्शक बनकर राष्ट्र को लूटता हुआ देखते रहेंगे? व्यक्ति और व्यवस्था के समवेत सुधार से ही समाज में बदलाव आ सकता है। व्यवस्था को संचालित करने वाले हाथ जब तक पवित्र नहीं होंगे, तब तक व्यवस्था को बदलना भी अपर्याप्त होगा। लोकतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए योग्य प्रत्याशी का चयन जरूरी है। जिस तरह विभिन्न परीक्षाओं में मापदंड जरूरी होता है, उसी तरह राजनीति में भी योग्यता का मापदंड निश्चित होना चाहिए। वोट उसी को दें, जो ईमानदार हो, नाशमुक्त हो, जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता से दूर हो तथा राष्ट्रीय एकता, मानवीय मूल्यों और सामाजिक सौहार्द में जिसका विश्वास हो। व्यक्ति जिस तरह अपनी बेटी का हाथ थमाते समय विचार करता है उसी प्रकार वोट देते समय भी विचार कर ही अपना वोट देना चाहिए।

राजनीतिक दल अपने-अपने ढंग से चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। गठबंधनों की बातें ही नहीं हो रहीं, गठबंधनों की रणनीतियां तैयार होने लगी हैं। दलबदल हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल समीकरण बनाने-बिठाने की जोड़तोड़ में जुट गये हैं। कुछ राष्ट्रीय दलों में घमासान मचा हुआ है, तो कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के लिये ये चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बने हुए हैं। इन स्थितियों के बीच मतदाता को भी जागरूक होना है। आने वाले चुनाव में मतदाता इतने सशक्त रूप में अपनी भूमिका को प्रस्तुत करें कि राजनीतिक दल चुनाव के बाद उसकी अनदेखी करने का दुस्साहस न कर सके। यहां तक कि मतदाता को लुभाने की कोशिशें और उसे भरमाने के प्रयासों से भी राजनैतिक दल उपरत हों, यही वर्तमान की सबसे बड़ी अपेक्षा और एक सशक्त संदेश है। राजा और प्रजा, शासक और शासित की यह व्यवस्था सदैव रही है और सदैव रहेगी। पद्धतियां बदलती रहती हैं। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था और अब 'मत पेटी' से पैदा होता है। इसीलिये जनतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनाव है। यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब है। जनतंत्र में स्वस्थ मूल्यों को बनाये रखने के लिए चुनाव की स्वस्थता और उसमें आम मतदाता की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। राजनीतिक दलों से पहले मतदाता को जागना होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-39)

गतांक से आगे...

जो व्यक्ति भाव अभाव से मुक्ति प्राप्त कर सका है, जन्म-मृत्यु से परे है, जहाँ पर सभी संकल्प सम्यक् रूप से शान्ति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे रागविहीन तथा रमणीक पद का अवलम्बन ग्रहण करो। यह पवित्र, निष्काम, दोषरहित ब्राह्मी स्थिति है। इसको स्वीकार करके विहार करता हुआ मनुष्य विपत्तिकाल में भी मोहग्रस्त नहीं होता। शास्त्रों के ज्ञान से या फिर वैराग्य से और महान् सद्गुणों के द्वारा जिस संकल्प को विनष्ट किया जाता है, उससे मन स्वत: ही उन्नतावस्था को प्राप्त होने लगता है। निराशा के वश में हुआ जो मन वैराग्य के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वही आशान्वित होने पर शरत्कालीन ऋतु में स्वच्छ सरोवर की भाँति राग युक्त हो जाता है; किन्तु भोगों से विरक्त हुए मन को बार-बार प्रत्येक दिन रागादि व्यापारों में डालते हुए ज्ञानी पुरुष लज्जित क्यों नहीं होते? चित् एवं विषय का योग ही बन्धन कहलाता है। उस योग से छुटकारा प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है।

निश्चय पूर्वक विषयरहित चित् को ही आत्मा कहा गया है, यही समस्त वेदान्त सिद्धान्त का सार है। इस विचार को सत्य मानकर प्रदीप्त अन्त:करण के द्वारा स्वयमेव अपने आप को देखो। इसमें असीम आनन्द पद की प्राप्ति होगी। मैं चित् स्वरूप हूँ। ये समस्त लोक चित् हैं, दिशाएँ एवं ये सभी प्राणि समुदाय भी चित् स्वरूप हैं। दृश्य एवं दर्शन से छुटकारा प्राप्त करके, मात्र परिष्कृत स्वरूप वाला साक्ष्यरूप चिदात्मा आभासरहित एवं नित्य प्रादुर्भूत होकर द्रष्टा बन रहा है।

मैं विषय वासनाओं से मुक्त होकर पूर्णरूपेण ज्योतिरूप होकर समस्त संवेदना से पूरी तरह से मुक्त होकर चित्स्वरूप और महान् संवित् (ज्ञानमय) हूँ। हे मुने! सभी संकल्पों को पूर्णरूपेण शान्त करके, सभी कामनाओं को त्यागकर निर्विकल्प पद में प्रविष्ट होकर आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाओ।

जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इस महोपनिषद् का प्रतिदिन पाठ करता है, वह यदि अश्रोत्रिय होता है, तो श्रोत्रिय हो जाता है। यदि वह उपनीत नहीं है, तो उपनीत (सदृश) हो जाता है। वह अग्नि के समान पवित्र होता है, वायु की भाँति परिष्कृत तथा वह सोमपूत और सत्यपूत हो जाता है। वह सर्वथा पूर्णशुद्ध हो जाता है। वह समस्त देवों में सुपरिचित हो जाता है। उसे सभी तीर्थ स्थलों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। वह सभी यज्ञों का अनुष्ठान संकल्प कर लेने में समर्थ हो जाता है।

क्रमश: ..

हिन्दू राष्ट्रवाद के समर्थक और तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ थे पं. मालवीय

मृत्युंजय दीक्षित

पंडित मदन मोहन मालवीय महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद् ही नहीं बल्कि एक बड़े समाज सुधारक भी थे जिन्होंने देश से जाति प्रथा की बेड़ियां तोड़ने के लिए कई प्रयास किए। पच्चीस दिसंबर 1861 में इलाहाबाद में जन्मे पंडित मदन मोहन मालवीय अपने महान कार्यों के चलते महामना कहलाए। वह तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहली बार वह 1909 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1910 तक इस पद पर रहे। दूसरी बार 1918 से 1919 और तीसरी बार उन्होंने 1932 से 1933 तक अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाली।

जुलाई 1887 से जून 1889 तक हिंदी दैनिक हिन्दोस्थान(कालांकर) के मुख्य संपादक,जुलाई 1889 से 1992 तक अंग्रेजी पत्र इण्डियन यूनियन के सह संपादक और 1907 में साप्ताहिक अभ्युदय 1909 में अंग्रेजी दैनिक लीडर 1910 में हिंदी पाक्षिक मर्यादा एवं 1933 में हिंदी साप्ताहिक सनातन धर्म के संस्थापक तथा कुछ वर्षों तक इन सभी पत्रों के संपादक रहे। मालवीय जी 1924 से 1940 तक हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली के चेयरमैन रहे। मालवीय जी ने 1908 में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन, प्रयाग के अध्यक्ष पद से समाचार पत्रों की स्वतंता का हनन करने वाले सरकारी प्रेस एक्ट तथा न्यूज पेपर एक्ट की कड़ी आलोचना की थी। सन 1910 में

मालवीय जी ने प्रान्तीय कौंसिल में सरकारी प्रेस विधेयक का कड़ा विरोध किया। जनचेतना एवं जनआंदोलन की लहर जगाने में महामना की पत्रकारिता ने एक बड़ी भूमिका निभायी थी। उनके लिये पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं अपितु एक धर्म था। वे पत्रकारिता को एक कला मानते थे।

हिंदू धर्म व समाज पर जब भी कोई संकट आता तो वे तुरंत सक्रिय हो जाते थे। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के लिए 24 घंटे कार्यरत रहते थे। उन्होने 10 अक्टूबर 1910 को काशी में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की और अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सभी से हिंदी सीखने का आह्वान किया। 19 अप्रैल 1919 को बम्बई में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मालवीय जी ने देवनागरी लिपि में लिखी गयी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान करने पर जोर दिया। मालवीय जी भारतीय विद्यार्थियों के लिए प्राचीन भारतीय दर्शन, साहित्य, संस्कृति और अन्य सुविधाओं के साथ- साथ अर्वाचीन नीतिशास्त्र, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, विधि विज्ञान, अर्थशास्त्र और राजनीति का अध्ययन आवश्यक समझते थे। हिंदी की सेवा और गोरक्षा में उनके प्राण बसते थे।

उन्हें एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वह 1912 में इंपीरियल लेजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य बने। 1919 में इसे सेंट्रल लेजिसलेटिव असेंबली के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और मालवीय जी 1926 तक इसके सदस्य रहे। इतिहासकार वीसी साहू के अनुसार हिन्दू राष्ट्रवाद के समर्थक मदन मोहन मालवीय देश से जातिगत बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने दलितों के मंदिरों में प्रवेश निषेध की बुराई के खिलाफ देशभर में आंदोलन चलाया। मालवीय ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय, जवाहर लाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर साइमन कमीशन का जबर्दस्त विरोध किया और इसके खिलाफ देशभर में जनजागरण अभियान चलाया। महामना तुष्टीकरण की नीतियों के खिलाफ थे। उन्होंने 1916 के लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का विरोध किया। वह देश का विभाजन नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने गांधी जी को आगाह किया था कि वह देश के बंटवारे की कीमत पर स्वतंत्रता स्वीकार न करें। मालवीय जी ने कई अखबारों की स्थापना की और सत्यमेव जयते के नारे को जन जन में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व किया। वह आजीवन देश सेवा में लगे रहे और 12 नवम्बर 1946 को उनका निधन हो गया।

नीतीश ने बिहार में 75 फीसदी आरक्षण कैसे दे दिया

अभिनय आकाश

आरक्षण किसी के लिए नौकरी पाने की उम्मीद है तो किसी की किसी के लिए यह नौकरी में बराबरी का मौका ना मिलने की वजह है। जो विरोध करते हैं उनके अपने तर्क हैं जो समर्थन करते हैं उनके अपने। जिस मकसद से आरक्षण लागू किया गया क्या वह पूरा हुआ? जवाब है- नहीं, अगर हो जाता तो वर्तमान में इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं होती। 1990 के दशक में मंडल कमीशन आया फिर आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्रीमी लेयर का सिद्धांत। लेकिन इन दिनों आरक्षण को लेकर जो चर्चा चल पड़ी है। बिहार में नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चला है। नीतीश कैबिनेट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर नई घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी आरक्षण 10 फीसदी दिया जाए। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण के बाद अब 75 फीसदी तक आरक्षण का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने बिहार में रखा है। नीतीश कैबिनेट ने जाति आधारित आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी कर दिया है। इसके अलावा 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलेगा। बिहार में अब आरक्षण लिमिट 75 फीसदी होने जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नीतीश कुमार का ये दांव कितना प्रैक्टिकल है और इससे पहले किन राज्यों ने भी इसी तरह की पहल की है।

शीर्ष अदालत ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में 1992 के अपने ऐतिहासिक फैसले में जिसे मंडल आयोग के फैसले के रूप में जाना जाता है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत

कर दी। अदालत की नौ-न्यायाधीशों की पीठ उस समय गठित सबसे बड़ी पीठ थी। शीर्ष अदालत ने पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखते हुए, उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षित करने की सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। फैसले में क्रीमी लेयर की अवधारणा भी सामने आई। क्रीमी लेयर को इस प्रकार परिभाषित किया गया था। पिछड़े वर्ग के कुछ सदस्य जो उस समुदाय के बाकी सदस्यों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से उन्नत हैं। वे उस विशेष पिछड़े वर्ग के अगड़े वर्ग का गठन करते हैं और उस वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण के सभी लाभों को खा जाते हैं, वास्तविक पिछड़े सदस्यों तक लाभ पहुंचने की अनुमति दिए बिना।

1992 के फैसले के बाद से, कई राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अब बिहार ने आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक करने के लिए कानून पारित किया है। फिर, 2019 में केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया। 8 और 9 जनवरी, 2019 को, लोकसभा और राज्यसभा ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया, जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के गरीबों को शामिल नहीं किया गया। इसने एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण के अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आवंटित किया। इससे विधेयक के खिलाफ दायर की जाने वाली याचिकाओं की बाढ़ आ गई। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसले में 2019 के 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अदालती कार्यवाही की अध्यक्षता के अपने आखिरी दिन 3:2 से कहा कि कानून भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, दो न्यायाधीशों, जिन्होंने इसके खिलाफ फैसला सुनाया, ने माना कि एससी, एसटी और ओबीएस के गरीबों को इसके दायरे से बाहर करने के कारण संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव के रूपों को प्रतिबंधित करता है। केंद्र ने स्वयं अदालत के समक्ष तर्क दिया है कि 50 प्रतिशत फैसला पत्थर की लकीर नहीं है।

नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कोटा में वृद्धि जाति सर्वेक्षण के बाद हुई है जो इस सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नौ दलों के बीच आम सहमति बनने के बाद आयोजित किया गया था। सर्वेक्षण ने हमें व्यापक डेटा प्रदान किया है। हम इसका उपयोग समाज के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए और अधिक उपाय पेश करने के लिए करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर केंद्र भी देश भर में जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने पर सहमत हो जाए। विधेयकों के अनुसार, एसटी के लिए कोटा दोगुना कर दिया जाएगा, एक से दो प्रतिशत, जबकि एससी के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाएगा। ईबीसी के लिए, कोटा 18 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि ओबीसी के लिए यह 12 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगा। जद (यू) नेता ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नई मांग उठाई और कहा कि प्राचीन काल में हमारी भूमि इतनी उन्नत थी। ऐतिहासिक कारकों के कारण इसमें स्थिरता आ गई। हमें अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने के लिए कुछ मदद की जरूरत है।

अभी 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति को 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। वहीं 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को दिया जाता है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रवाधान साल 2019 में किया गया। 1963 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आमतौर पर 50 फ़ीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ हमें मेरिट का ख़्याल रखना होगा तो दूसरी तरफ हमें सामाजिक न्याय को भी ध्यान में रखना होगा।

महाराष्ट्र में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया। तमिलनाडु में सबसे अधिक 69 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है। वहां पर रिजर्वेशन संबंधित कानून की धारा-4 के तहत 30 फीसदी आरक्षण पिछड़ा वर्ग, 20 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग, 18 फीसदी एससी और एक फीसदी एसटी के लिए रिजर्व किया गया।

आज का इतिहास

1970 ओरेगन हाईवे डिवीजन ने असफलता के साथ फ्लोरेंस, ओरेगन के पास समुद्र तट शुक्राणु व्हेल को विस्फोटकों के साथ नष्ट करने का प्रयास किया।

1991 पूर्वी तिमोर में, इंडोनेशियाई बलों ने पूर्वी तिमोर पर कब्जे के विरोध में छात्रनेताओं पर गोलियां चला दीं, जिसमें 250 लोगों की मौत हो गई।

1996 एक सऊदी अरब एयरलाइंस बोइंग 747 और एक कजाखस्तान एयरलाइंसकार्गो विमान नई दिल्ली के पास मध्य हवा में टकरा गए, जिससे 349 लोग मारे गए।

2001 न्यूयॉर्क में अमेरिकी एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 260 यात्री मारे गए।

2005 संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान इराक की एक आश्चर्यजनक यात्रा का भुगतान करते हैं और एक अरब लीग सम्मेलन के लिए समर्थन का समर्थन करते हैं, जो इराक के कई दलों के साथ सहयोग पर चर्चा करता है।

2006 अंतराष्ट्रीय संधि प्रोटोकॉल ऑन एक्सप्लोसिव रेमनेन्ट्स ऑफ वार लागू हुई।

2006 इजरायल ने ईरान को अंतिम उपाय के रूप में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले करने के लिए धमकी दी है। ईरान का विदेश मंत्रालय इस बात का प्रतिकार करता है कि यदि ईरान इस निर्णय के साथ आगे बढ़ता है तो वह कुचलने वाले हमले का प्रतिकार करेगा।

2007 एक 16 वर्षीय स्पेनिश विरोधी नस्लवाद उदारवाद की हत्या मैड्रिड में हुए एक आप्रवासन विरोधी विरोध के बीच की गई है।

2009 2 जापानी पनडुब्बियां जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूब गईं थीं, उन्हें ओहू, हवाई से दूर पाया गया है।

2010 गंभीरता के उपायों के एक हिस्से के रूप में इसे सांस्कृतिक बजट में कटौती करने के प्रयास में, सरकार ने इटली में प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षणों को बंद कर दिया है।

2014 चीनी नेता शी जिनपिंग और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ग्रीनहाउस गैसों को सीमित करने के लिए एक समाधान पर पहुंचे हैं।

एमपी व राजस्थान में समीकरण बिगाड़ेगी पुरानी पेंशन

जितेंद्र भारद्वाज

पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर केंद्र और विभिन्न प्रदेशों के कर्मचारी संगठन अब लामबंद हो चुके हैं। ओपीएस की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में तीन रैलियां आयोजित की गई हैं। चौथी रैली दस दिसंबर को होगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कहते हैं, पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। खासतौर पर, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में सरकारी कर्मियों का वोट, सत्ता समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। तीनों ही राज्यों में एनएमओपीएस के बैनर तले वोट फॉर ओपीएस कैंपेन और मतदाता जागरूकता अभियान शुरु किया गया है। अगर सरकारी कर्मियों और उनके परिवार को मिलाएं तो हर विधानसभा क्षेत्र में 25000 वोट टर्निंग प्वाइंट बनने जा रहे हैं।

विजय कुमार बंधु ने शनिवार को बताया, राजस्थान और मध्यप्रदेश, इन दोनों प्रदेशों में अगर यूं कहें कि पुरानी पेंशन का मुद्दा एक टर्निंग प्वाइंट बन चुका तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सरकारी कर्मियों की संख्या तो कम है। ऐसे लोगों के लिए इतना ही कहा सकता है कि वे केवल संख्या को देख रहे हैं, उसके पीछे जो फैक्टर है, वे उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। जब वोट गिरेंगे तो यही फैक्टर निर्णायक बन जाएगा। अगर किसी गांव में दो टीचर हैं और वे अपना मुद्दा रखने में सक्षम हैं तो पूरा गांव, उनकी मांग यानी ओपीएस पर विचार कर सकता है। राजस्थान और मध्यप्रदेश के किसी भी विधानसभा क्षेत्र को ले लें, वहां पर कम से कम पांच हजार सरकारी कर्मियों की संख्या है। कुछ रिटायर्ड कर्मी भी हैं। अगर हम केवल सर्विंग कर्मियों की बात करें तो उनके परिवार को मिलाकर वह औसत संख्या 25 हजार हो जाती है। विधानसभा चुनाव, जहां कांटे की टक्कर होती है, वहां पर पांच सौ वोट भी जीत हार तय करने के लिए काफी होते हैं। यहां तो बात पच्चीस हजार वोटों की हो रही है।

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार, दोनों ही राज्यों में पचास से ज्यादा सीटों को इधर-उधर करने में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा, अहम भूमिका निभाएगा। दोनों ही राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों का कोर वोटर भी अब ओपीएस की बात कर रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा शुरु किए गए जागरूकता अभियान का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारी, अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए वोट करेंगे। राजनीतिक दल,

हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में ओपीएस का असर देख चुके हैं। मध्यप्रदेश की बात करें तो वहां पर लगभग छह लाख ऐसे कर्मचारी हैं, जो एनपीएस में हैं। अगर रिटायर्ड कर्मियों की बात करें तो उनकी संख्या भी तकरीबन छह लाख है। भले ही रिटायर्ड कर्मी, ओपीएस में हैं, लेकिन वे भी एनपीएस कर्मियों का साथ दे रहे हैं। रेलवे और दूसरे केंद्रीय महकमों के कर्मियों व उनके परिजनों को मिलाकर यह संख्या डेढ़ दो लाख हो जाती है। वोटिंग के दौरान यह संख्या अपना असर दिखाएगी। इसी तरह अगर राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी नौ से दस लाख सर्विंग/रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य हैं। चुनाव में सत्ता के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने के लिए यह संख्या काफी है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड, जस्टिस बीडी तुलजापुरकर, जस्टिस ओ. चिन्नप्पा रेड्डी एवं जस्टिस बहारुल इस्लाम शामिल थे, के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट पिटीशन संख्या 5939 से 5941, जिसको डीएस नाकरा एवं अन्य बनाम भारत गणराज्य के नाम से जाना जाता है, में दिनांक 17 दिसंबर 1981 को दिए गए प्रसिद्ध निर्णय का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैरा 31 में कहा गया है, चर्चा से तीन बातें सामने आती हैं। एक, पेंशन न तो एक इनाम है और न ही अनुग्रह की बात है जो कि नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर हो। यह 1972 के नियमों के अधीन, एक निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। पेंशन, अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में, नियोक्ता के इस आश्वासन पर लगातार कड़ी मेहनत की है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ दिया जाएगा।

एनपीएस में कर्मियों जो पेंशन मिल रही है, उतनी तो बुढ़ावा पेंशन ही है। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी, 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है। एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 49 सौ रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिली है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह क्रमशः 15250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का दस प्रतिशत शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है। इस शेयर को 14 या 24 प्रतिशत तक बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। एआईडीईएफ के महासचिव सी.श्रीकुमार के मुताबिक, एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का भी कोई प्रावधान नहीं है। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते हैं, उन्हें महंगाई राहत के तौर पर आर्थिक फायदा मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं रही।

केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन, पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो ट्रेनें थम जाएंगी, टैंक/हथियार बनाने वाली मशीन बंद होंगी और सरकारी कर्मचारी कलम छोड़ देंगे। केंद्र और राज्यों के कर्मचारी अब कुछ ऐसे ही कठोर कदमों पर चलने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि ऐसे कठोर कदमों की सटीक जानकारी 21 नवंबर के बाद ही मिल सकेगी। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी.श्रीकुमार ने बताया, सरकार इस मामले पर अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी संगठन, राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सकते हैं। इसके लिए 20 और 21 नवंबर को देशभर में स्ट्राइक बैलेट होगा। कर्मचारियों की राय ली जाएगी। अगर दो तिहायी बहुमत हड़ताल के पक्ष में होता है तो केंद्र एवं राज्यों में सरकारी कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उस अवस्था में रेल थम जाएंगी, आयुद्ध कारखाने, जो अब निगमों में तबदील हो चुके हैं, वहां पर काम बंद हो जाएगा। केंद्र एवं राज्यों के सरकारी कर्मचारी कलम छोड़ देंगे।

मध्यप्रदेश में भाजपा के लिए कई चुनौतियां

अंकित सिंह

भोपाल के बगल में सीहोर में शिवराज सिंह चौहान के गढ़ से लेकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा तक मतदाताओं में मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से हलचल देखी जा सकती है। चार बार सत्ता में रहने के बाद भी भाजपा जीत की उम्मीद कर रही है। हालांकि, पार्टी को एंटी इनकन्वेंसी से मुकाबला करना होगा। दूसरी ओर कांग्रेस को उम्मीद है कि भाजपा के सत्ता विरोधी लहर का उसे फायदा होगा। यही कारण है कि कांग्रेस की ओर से लगातार भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर लगाए जा रहे हैं। दोनों पार्टियों की ओर से चुनावी वादों की भी बौछार की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर चुनावी वादों में लोगों को सीधे नगदी राहत पहुंचाने की बात कही गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे क्या कुछ मध्य प्रदेश में होने वाला है? हिंदुत्व की राह पर चलते हुए भाजपा ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत रखी है। भाजपा लगातार दावा कर रही है कि उसने मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का टैग हटा दिया है। अब मध्य प्रदेश में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया गया है। हालांकि, भ्रष्टाचार के भी कई बड़े आरोप लगे हैं। भाजपा यह भी दावा करती है की नगदी और सब्सिडी के माध्यम से लोगों को राहत भी पहुंचाई जा रही है। इसके लिए भाजपा लाडली बहना योजना, गरीबों को मुफ्त राशन जैसे योजनाओं को गिना भी रही है। 2018 में हुए चुनाव में कांग्रेस राज्य में आगे जरुर रही थी लेकिन मत प्रतिशत के मामले में वह भाजपा से पीछे थी। शिवराज सरकार की सबसे चर्चित लाडली बहन योजना में महिलाओं को मिलने वाली 1250 रुपए प्रति माह की राशि को बढ़ाकर भाजपा ने 3000 रुपये करने का ऐलान किया है जबकि कांग्रेस ने 500 रुपये में सिलेंडर और महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक सहायता देने का वादा किया है। हालांकि राज्य के राजनीतिक विश्लेषक इस बात से इतर उन मुद्दों को भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो मतदाताओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में है। मध्य प्रदेश में फिलहाल भ्रष्टाचार और रोजगार बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक की वजह से छात्रों को परेशानी हुई है और यही कारण है कि कांग्रेस से लगातार सत्ता में आने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। कई जगह पर लोगों का मानना है कि पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी को देखकर इस बार हम अपना वोट डालेंगे। मीडिया में जो रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक भी राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जितनी ज्यादा नाराजगी नहीं है, उससे ज्यादा नाराजगी स्थानीय विधायकों से है। व्यापम भर्ती घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा हाल में हुए पटवारी घोटाले में भी भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ गई है। भाजपा राज्य में राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी भाजपा को राष्ट्रीय मुद्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा को राज्य में किए गए कामों को बताना चाहिए और राज्यों के मुद्दों पर ही यह चुनाव लड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि लाडली बहना योजना भाजपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है। हालांकि कैश एंड डिलीवरी मॉडल को लेकर भी मतदाताओं में असंतोष है। लोगों का मानना है कि किसी भी सरकार को देश हित और राज्यहित पर ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए।

रोजगार के लिए एक-दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही भाजपा और कांग्रेस

''हम मजदूरी के लिए गुजरात नहीं जाएं, तो और क्या करें, पथरीली जमीन होने से खेत में फसल कम पकती है। खेती से किसी तरह बस अपने गुजारे लायक अनाज मिल पाता है।'' आदिवासी किसान रण सिंह (60) यह जवाब देते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि झाबुआ जिले के लोग बड़ी तादाद में रोजी-रोटी के लिए पड़ोस राज्य गुजरात का रुख क्यों करते हैं? झाबुआ के जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ''फलिये'' (छितरी हुई बसाहट जिनमें घाटियों पर घर बने होते हैं) में रहने वाले रण सिंह रबी फसल की बुआई के लिए इन दिनों अपना छोटा-सा खेत तैयार कर रहे हैं। प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के प्रचार की चरम पर पहुंचती सरगर्मियों से दूर इस ''फलिये'' में खामोशी है, लेकिन रोजगार के लिए आदिवासियों का पलायन झाबुआ सीट का अहम मुद्दा है। जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित यह सीट लम्बे समय तक कांग्रेस का गढ़ रही है। रण सिंह आदिवासियों के भील समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने स्थानीय बोली में बताया,''मैं खुद कई साल पहले कपास चुनने के लिए गुजरात गया था। हालांकि, मैं बाद में खेती के लिए अपने फलिये में लौट आया, लेकिन फलिये के हर घर से एक-दो लोग मजदूरी के लिए अब भी गुजरात में हैं।'' आदिवासी किसान ने बताया कि उनके फलिये के आस-पास के इलाकों में 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। उन्होंने बताया,''गुजरात में इससे ज्यादा दिहाड़ी मिलती है, लेकिन इसके लिए हमें वहां रात-दिन काम करना पड़ता है।'' कुल 3.13 लाख मतदाताओं वाली झाबुआ सीट से कांग्रेस ने युवा कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को चुनाव मैदान में उतारा है जिनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी भानु भूरिया से है। पेशे से चिकित्सक विक्रांत, झाबुआ सीट के मौजूदा विधायक कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं। कांतिलाल की गिनती देश के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं में होती है और वह कांग्रेस की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। झाबुआ से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत ने आरोप लगाया कि सूबे में भाजपा के 18 साल के राज के दौरान इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा, '' राजग सरकार की शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से झाबुआ में आदिवासियों का पलायन बड़े स्तर पर रुका था, लेकिन पिछले दो-तीन सालों से मनरेगा के तहत आदिवासी मजदूरों को भुगतान होने में मुश्किल पेश आ रही है और वे पलायन के लिए मजबूर हैं।'' भाजपा उम्मीदवार भानु भूरिया ने कहा, '' विक्रांत के पिता कांतिलाल भूरिया झाबुआ से पिछले 45 साल से चुनकर लोकसभा और विधानसभा पहुंचते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र से पलायन रोकने पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर भूरिया कांग्रेस के राज में झाबुआ में नदियों पर बांध बनवा देते, तो आदिवासी किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाता जिससे रोजगार के लिए उनके पलायन पर रोक लग सकती थी।''

छत्तीसगढ़ के कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर

दुष्यंत शर्मा

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 20 सीटों पर मतदान होने के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौर में कितनी सीटें किसके पाले में गईं। इसके साथ ही सबकी नजर बची हुईं 70 सीटों पर है। दूसरे दौर में राजधानी के रण पर सबकी नजर होगी क्योंकि यहां प्रदेश की राजनीति में खासा दखल रखने वाले नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। जिले की छह सीटों पर कांग्रेस और एक पर भाजपा का कब्जा है।

जिले का सियासी गणित समझने के लिए शहर के रजबंधा मैदान स्थित किसी भी चाय की दुकान पर थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा। एक दुकान पर मिले शिक्षक गोरेलाल जॉनसन ने बताया, लड़ाई इस बार कांटे की है। रायपुर पश्चिम में भाजपा ने पूरा जोर लगा रखा है। डॉ. राजेश ने रायपुर उत्तर में सिंधी समाज की नाराजगी से कांग्रेस को नुकसान बताया। रायपुर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूत माना लेकिन उनकी सफलता पर संशय भी जाहिर किया। शहरी मतदाता रेवड़ी संस्कृति से नाराज हैं तो ग्रामीण इसे बड़ी राहत मानते हैं। एक ढाबे पर एक फैक्टरीकर्मी परमेश्वर शर्मा ने कहा, शहर के सभी विकास कार्य भाजपा के समय हुए। कांग्रेस राज में कोई नया काम नहीं शुरू हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के शिव साहू ने कहा, कांग्रेस ने गांव और किसान का ख्याल रखा। हालांकि, बिजली बिल माफी और बेरोजगारी पर उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाई।

रायपुर दक्षिण- सीट से 1990 से लगातार सातवीं बार विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को आठवीं जीत से रोकने के लिए कांग्रेस ने दूधाधारी मठ के मठाधीश महंत रामसुंदर दास को मैदान में उतारा है। शहर में दोनों नेताओं की अच्छी पकड़ होने के नाते मुकाबला दिलचस्प

है। समर्थकों का मानना है कि इस बार मुकाबला काफी करीबी होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी महंत रामसुंदर दास वर्तमान में गोसेवा आयोग के अध्यक्ष हैं।

रायपुर ग्रामीण- कांग्रेस ने सात बार के विधायक 80 वर्षीय सत्यनारायण शर्मा की जगह बेटे पंकज शर्मा को यहां से उतारा है। 1985 में पहली बार चुने गए सत्यनारायण इस सीट से सिर्फ एक बार 2008 में हारे थे। उनके बेटे पंकज भी दो दशक से अधिक समय से संगठन से जुड़े हैं। भाजपा ने पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल साहू को उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। यहां ओबीसी मतदाता निर्णायक हैं।

आरंग- इस बार मंत्री शिवकुमार डहरिया की राह आसान नहीं है भाजपा ने उनके खिलाफ सतनामी समाज के धर्मगुरु बालदास के पुत्र गुरु खुशवंत सिंह को मैदान में उतारा है। गुरु बालदास पहले कांग्रेस में थे। वह इसी साल भाजपा के पाले में आए और बेटे को टिकट दिलाने में भी सफल रहे। क्षेत्र में सतनामी मतदाताओं का अच्छा प्रभाव है।

रायपुर उत्तर- कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार कुलदीप जुनेजा को टिकट देकर सिंधी समाज की नाराजगी मोल ले ली है। नाराज अजीत कुकरेजा बागी होकर मैदान में हैं। वहीं, भाजपा ने छत्तीसगढ़ सर्व उड़िया समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा पर दांव खेलकर जुनेजा को घेरने की कोशिश की है। समाजसेवी की छवि वाले पुरंदर के उड़िया समाज के मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है।

रायपुर पश्चिम- भाजपा के पूर्व मंत्री रहे राजेश मूणत और कांग्रेस से वर्तमान विधायक विकास उपाध्याय आमने-सामने हैं। पिछले चुनाव में मूणत की लगातार तीन जीत का क्रम तोड़ते हुए विकास ने सफलता हासिल की थी। संसदीय सचिव विकास क्षेत्र में सक्रियता के चलते लोकप्रिय हैं।

धरसींवा- कांग्रेस ने विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा का टिकट काटकर पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा को उतारा है। उनके मुकाबले में भाजपा ने छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सितारे पद्मश्री अनुज शर्मा की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण में 253 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इस सूची में डिप्टी सीएम वरिष्ठ कांग्रेसी टीएस सिंहदेव 447 करोड़ के साथ शीर्ष पर हैं। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में 953 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पांच उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण नहीं किया जा सका क्योंकि वे ठीक ढंग से स्कैन नहीं किए गए थे या फिर अधूरे थे। रिपोर्ट के अनुसार उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब दो करोड़ है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस के 70 में से 60 (86त्न) उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 70 में से 57 (81त्न) उम्मीदवार, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के 62 में से 26 (42%) उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी (आप) के 44 में से 19 (43त्न) उम्मीदवारों ने एक करोड़ से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है।

राजस्थान विधानसभा चुनावों में बागियों के भंवर में फंस गयी है भाजपा

रमेश सर्राफ धमोरा

राजस्थान में आगामी 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में राज बदलने के प्रयास में लगी भाजपा में बड़ी संख्या में बागी प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने संकट पैदा हो रहा है। राजस्थान में भाजपा ने इस बार बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों, पूर्व विधायकों व पिछले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके लोगों के टिकट काटकर उनके स्थान पर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने दूसरे दलों से आये दलबदलुओं को भी बड़ी संख्या में टिकट देकर उपकृत किया है, जिससे पार्टी में बगावत तेज हो गई है।

अपने टिकट कटने से नाराज भाजपा सरकार में मंत्री रहे तीन बड़े नेताओं ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। इससे भाजपा प्रत्याशियों के समक्ष संकट व्याप्त हो गया है। वसुंधरा राजे के खासमखास रहे पूर्व मंत्री यूनुस खान ने डीडवाना, बंशीधर बाजिया ने खंडेला व कैलाश मेघवाल ने शाहपुरा से निर्दलीय ताल ठोक दी है। हालांकि कैलाश मेघवाल को कुछ दिनों पूर्व ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। इसके अलावा भाजपा में डग विधानसभा से पूर्व विधायक रामचंद्र सुनारीवाल, सांचौर सीट पर जालौर के सांसद देवजी पटेल के सामने पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी, चित्तौड़गढ़ सीट पर विद्याधर नगर से मौजूदा विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी के सामने चित्तौड़गढ़ के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने नामांकन दाखिल कर दिया है।

बाड़मेर से पूर्व मंत्री गंगाराम चौधरी की पोती प्रियंका चौधरी ने बगावत कर दी है। प्रियंका चौधरी पिछली बार पार्टी की प्रत्याशी रही थीं। मगर पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के नजदीकी होने के चलते उनकी टिकट काट दी गई है। सूरतगढ़ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भादू और बयाना से पूर्व प्रत्याशी रितु बनावत ने ताल ठोक दी है। रितु बनावत के पति ऋषि बंसल को भरतपुर के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। बंसल पूर्व में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

कोटा जिले की लाडपुरा सीट पर तीन बार विधायक रह चुके भवानी सिंह राजावत ने दूसरी बार टिकट नहीं मिलने पर मैदान में ताल ठोक दी हैं। 2018 में भवानी सिंह राजावत का टिकट काटकर कोटा राजघराने की कल्पना देवी को भाजपा प्रत्याशी बनाया था। इस बार फिर लाडपुरा विधायक कल्पना देवी को ही प्रत्याशी बनाया गया है। इससे नाराज होकर भवानी सिंह राजावत ने निर्दलिय फॉर्म भर दिया है। झुंझुनूं विधानसभा सीट पर पिछली बार भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेंद्र भाम्भू के स्थान पर 2018 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े निषित कुमार को टिकट देने से नाराज होकर राजेंद्र भाम्भू निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर गए हैं।

पिलानी विधानसभा सीट पर सात बार विधायक व मंत्री रहे सुंदरलाल के पुत्र कैलाश मेघवाल का टिकट काट देने से उन्होंने भी पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भर दिया है। कैलाश मेघवाल पिछले विधानसभा चुनाव में पिलानी से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार गए थे। सीकर सीट पर भाजपा के

मौजूदा उप जिला प्रमुख ताराचंद घायल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फॉर्म भर दिया है। फतेहपुर सीट पर नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके मधुसूदन भिंडा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म भरा है।

कोटपूतली सीट पर पिछली बार के प्रत्याशी मुकेश गोयल, लूणकरणसर से प्रभूदयाल सारस्वत, सुजानगढ़ से राजेंदर नायक, मकराना से हिम्मत सिंह राजपुरोहित, सवाई माधोपुर से आशा मीणा, संगरिया से गुलाब सींवर, मसूदा से जसवीर सिंह खरवा, बस्सी सीट पर भाजपा सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जितेंद्र मीणा ने निर्दलिय फॉर्म भरा है। वहीं कपासन सीट पर राशमी पंचायत समिति प्रधान दिनेश बुनकर, गढ़ी सीट पर पूर्व प्रधान लक्ष्मण डिंडोर ने नामांकन फॉर्म भरकर भाजपा की धड़कनें बढ़ा दी हैं। मावली सीट पर भाजपा के कुलदीप सिंह चुंडावत ने पार्टी से बगावत कर आरएलपी से नामांकन भर दिया है। कुंभलगढ़ सीट पर भाजपा के नीरज सिंह राणावत, अनोप सिंह ने भी निर्दलीय नामांकन भरा है।

भाजपा ने चुनाव से पहले दूसरे दलों से दल-बदल कर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया को लक्ष्मणगढ़ से प्रत्याशी बनाया है जहां उनका मुकाबला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से होगा। कांग्रेस से सांसद रही ज्योति मिर्धा को भाजपा ने नागौर सीट पर मौजूदा विधायक सोहनलाल चौधरी का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया है। जहां उनका मुकाबला अपने ही चाचा व कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मिर्धा से होगा। ज्योति मिर्धा मारवाड़ के दिग्गज जाट नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती हैं। कोटपूतली से हंसराज पटेल, धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, खंडेला से सुभाष मील, वल्लभनगर से उदयलाल डांगी, करौली से दर्शन सिंह गुर्जर बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, सादुलपुर से सुमित्रा पूनिया को टिकट दिया गया है। सुमित्रा पूनिया कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया के पुत्रवधू हैं।

टोडाभीम सीट से रामनिवास मीणा को टिकट दिया गया है। पूर्वी नहर परियोजना को लेकर रामनिवास मीणा लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और क्षेत्र में पानी वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। शाहपुरा से उपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। उपेन यादव राजस्थान बेरोजगार महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष है व पिछले लंबे समय से युवा बेरोजगारों की राजनीति कर रहे हैं। भाजपा ने इस बार आदर्श नगर से अशोक परनामी और सिविल लाइन से अरुण चतुर्वेदी का भी टिकट काट दिया है। यह दोनों ही नेता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तथा वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। कहने को तो भाजपा में कई वसुंधरा समर्थकों को टिकट मिलने की बात की जा रही है। मगर जिस तरह से प्रह्लाद गुंजल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष घुटने टेक कर टिकट प्राप्त किया है उससे तो यही लगता है कि अब नाम को ही वसुंधरा समर्थक रह गए हैं। बाकी जिनको भी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है उन सबसे पार्टी के नाम पर वादे करवाए गए हैं। हालांकि वसुंधरा राजे स्वयं झालरापाटन से चुनाव लड़ रही हैं। मगर उनके बहुत से कट्टर समर्थकों को चुनावी मैदान से दूर कर भाजपा ने उन को उनकी औकात दिखा दी है।

अनुशासन के लिए विख्यात भाजपा में इस बार जिस तरह से टिकटों की बंदरबांट हुई है तथा दलबदलुओं को हाथों हाथ टिकट दी गई है। उससे पार्टी का चाल, चरित्र व चेहरा बेनकाब हो गया है। भाजपा में जो लोग वर्षों से काम कर रहे थे उनको भी इससे बहुत निराशा हुई है। जिस तरह से पार्टी ने टिकट बांटे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि भाजपा को चुनावी मैदान में कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ के चुनाव को त्रिशंकु बना पाएंगी ये क्षेत्रीय पार्टियां?

राज्य की स्थापना के बाद से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ का चुनाव दो ध्रुवों के बीच बंटा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच

केंद्रित रहने वाली इस लड़ाई में तीसरी ताकतों ने सेंध लगाने की कोशिशें तो जरुर कीं लेकिन उन्हें उस तरह की सफलता नहीं मिली कि वह पार्टियां इतनी सीटें बटोर लें कि सीटों के लिहाज से इस छोटे प्रदेश में वह किंग मेकर बन सकें या किसी प्रकार के मोल-भाव की स्थितियों में आ जाएं। 2003 के पहले विधानसभा चुनावों से लेकर 2018 के विधानसभा चुनावों तक जाति या किसी समाज के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली यह क्षेत्रीय पार्टियां सीट पाने के मामले में अब तक कोई बड़ी लकीर नहीं खींच सकी हैं। ना ही इन पार्टियों का प्रदर्शन इतना महत्वपूर्ण रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के माथे पर कोई राजनीतिक शिकन पड़े। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पार्टियां खेल बिगाड़ने की हैसियत नहीं रखतीं। छोटी-छोटी मार्जिन से होने वाली चुनावी जीत-हार में इन पार्टियों को मिला वोट कई बार निर्णायक साबित होता रहा है।

अजीत जोगी ने जब 2016 में कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई थी तब इस बात के कयास तेजी से लगने शुरू हुए थे कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ में त्रिंशकु के हालात होंगे। 2018 के चुनावों में पहली बार ऐसा लगा था कि राज्य में बीजेपी या कांग्रेस स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाएंगी। खुद अजीत जोगी अपनी सभाओं में इस बात का बारम्बार दावा करते थे कि बिना उनके राज्य में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अजीत जोगी की पार्टी ने बसपा के साथ समझौता किया। चुनाव में उनकी पार्टी को पांच और बसपा को दो सीटें मिलीं। यह सात सीटें महत्वपूर्ण हो सकती थीं लेकिन कांग्रेस को मिले प्रचंड बहुमत के बाद यह सात सीटें औचित्यहीन हो गईं।

कितनी मजबूत हैं आप और बसपा

अब छत्तीसगढ़ फिर से चुनावों के समर में हैं। बस्तर संभाग की बीस सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट पड़ने हैं। इस बार अजीत जोगी नहीं हैं। उनके पुरानी राजनीतिक पार्टनर बसपा का गठबंधन किसी और दल के साथ है। अमित जोगी राज्य की कुछ सीटों को छोड़कर करीब-करीब सभी पर ताल ठोंक रहे हैं। आम आदमी पार्टी दूसरी बार राज्य में चुनाव लड़ रही है। जाति और समाज की राजनीति करने वाले कुछ नए-पुराने खिलाड़ी नए दावों के साथ चुनावी समर में हैं। आइए समझते हैं कि क्या ये पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस की पारंपरिक सत्ता को चुनाती देते हुए इतनी सीटें बटोर सकती हैं कि यह दोनों राष्ट्रीय दल चुनाव के बाद इनके समर्थन के मोहताज हो जाएं। क्या राज्य में किसी भी तरह के त्रिंशकु के हालात बन सकते हैं?

अजीत जोगी के द्वारा बनाई गई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ इस बार 84 सीटों पर लड़ रही है। खुद अमित जोगी पाटन सीट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। 2018 के चुनाव में जोगी कांग्रेस, बसपा और सीपीआई के गठबंधन को 11 फीसदी वोट मिले थे। पांच सीटें अजीत जोगी की पार्टी को और दो सीटें बसपा को मिलीं थीं। इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। अजीत जोगी नहीं रहे। अजीत जोगी के साथ कांग्रेस छोड़कर आए बहुत सारे नेता या तो कांग्रेस में लौट गए या फिर उन्होंने कोई दूसरा ठिकाना तलाश लिया। बसपा इस बार जोगी की पार्टी के साथ नहीं है। इन बदले हुए

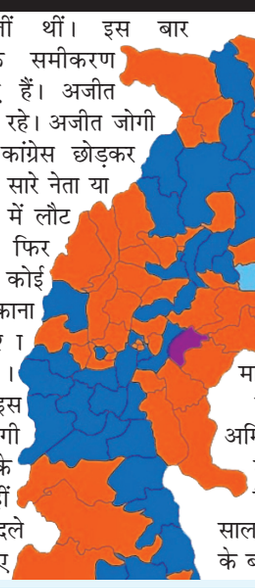

राजनीतिक हालातों पर जोगी की पार्टी किस तरह चुनाव का प्रबंधन कर रही है इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समालोचक दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि पिछले चुनाव में अजीत जोगी ऐसा माहौल रचने में सफल रहे थे जहां दोनों पार्टियों को यह लग रहा था कि अजीत कुछ सीटें जीतने में सफल हो सकते हैं। इस बार का माहौल ऐसा नहीं है।

राजनीतिक गलियारों में अमित जोगी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। टिकट देने में भी उन्होंने सात साल पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बजाय बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेताओं को चुना है। जिसमें ज्यादातर कांग्रेस के बागी हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वह कांग्रेस को असहज तो कर सकते हैं लेकिन वह चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण असर डाल पाएंगे ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वरिष्ठ टीवी पत्रकार बरुण सखाजी इसमें कुछ बातें और जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि अमित जोगी ने खुद पाटन सीट से लड़कर चुनाव को रोचक तो बना दिया है लेकिन पूरे प्रदेश में वह कोई माहौल बना पाए हैं ऐसा होता नहीं दिखता। ज्यादातर प्रत्याशी मुख्य लड़ाई से बाहर हैं। रेणु और रिचा जोगी की सीट खुद भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी है। हालांकि उन्हीं स्थिति बाकी उम्मीदवारों से बेहतर है।

कांशीराम के जमाने से ही राज्य में जड़े जमाने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार फिर से छत्तीसगढ़ में ताल ठोंक रही है। बीते चुनाव में अजीत जोगी की पार्टी से गठबंधन करने वाली बसपा इन चुनावों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ एलांयस में है। बसपा 58 तो गोडंवाना गणतंत्र पार्टी 32 सीटों पर लड़ रही है। बसपा का प्रभाव हमेशा से ही बिलासपुर संभाग में रहा है। प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां बसपा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध कहते हैं कि बसपा का आधार दलित है। पिछले दो चुनावों से उसकी कोशिश उस दलित वोट में आदिवासी वोटों को जोड़ने की है। 2018 के चुनावों में उसने अजीत जोगी की पार्टी से एलायंस किया। उसे दो सीटें मिलीं और कई सीटों पर उसके वोटों में भी इजाफा हुआ। इस बार उसने राजनीतिक पार्टनर बदल दिया है। आदिवासी वोटों में पैठ का दावा करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उसका गठबंधन है। अभी तक का जो माहौल राज्य में बन रहा है उसमें इस गठबंधन का प्रभाव सीमित सीटों पर दिख रहा है। हो सकता है कि कई सीटों पर वह मुख्य पार्टियों का नुकसान करे जिसमें कांग्रेस के नुकसान की संभावना ज्यादा है, लेकिन यह कहना मुश्किल होगा कि इस गठबंधन की सीटें इतनी

आएंगी कि वह बीजेपी या कांग्रेस को असहज करे। दिवाकर मुक्तिबोध इसकी वजह स्थानीय नेतृत्व का ना होना बताते हैं। राज्य में बसपा ऐसा कोई नेता विकसित नहीं कर पाई जो कुछ सीटों पर अपने प्रभाव को लगातार बनाकर रख पाया हो। जिन सीटों पर दलितों की संख्या कम है उन सीटों पर बसपा का कोई प्रभाव नहीं है। इसी तरह शहरी सीटों में भी बसपा का प्रभाव नहीं है। हीरा सिंह मरकाम के निधन के बाद यही हाल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का है।

इन दलों के अलावा कुछ और छोटी पार्टियां भी छत्तीसगढ़ के चुनावों में दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। बस्तर के भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में 22 हजार वोट पाकर चर्चाओं में आने वाली हमर राज पार्टी भी एक ऐसी दावेदार है। इस पार्टी के प्रमुख अरविंद नेताम एक दर्जन से अधिक सीटों पर पार्टी के दबदबे का दावा करते रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रांति सेना से बनी जोहार छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल ने प्रदेश की 46 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। वह 44 बिंदुओं पर अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी लॉन्च कर चुके हैं। इन छोटी पार्टियों की कोशिशों पर टीवी पत्रकार बरुख सखाजी कहते हैं कि उपचुनावों में यह पार्टियां जरुर दमखम दिखाती हैं लेकिन मुख्य चुनाव में जब चुनाव अपने निर्णायक मुकाम पर पहुंच जाता है तो उस दौड़ में यह पार्टियां पीछे छूटने लगती हैं। अभी के राजनीतिक वातारवरण को देखकर यह लगता है कि यह पार्टियां भले खुद सीटें ना जीते लेकिन वह दोनों बड़ी पार्टियों का नुकसान जरूर कर सकती हैं। इसमें ज्यादा नुकसान कांग्रेस का होना तय माना जा रहा है।

क्या बढ़ेगा वोट बैंक

218 के चुनाव परिणाम को देखा जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर 43 प्रतिशत था और बीजेपी का 32 प्रतिशत। बीजेपी और कांग्रेस के वोट में दस प्रतिशत का अंतर था। लेकिन मत प्रतिशत का यह अंतर सीटों में प्रतिबिंबित नहीं हुआ। कांग्रेस 67 सीटों पर चुनाव जीती और बीजेपी 15 सीटों पर अटक गई थी। उधर जोगी कांग्रेस,बसपा, सीपीआई के गठबंधन को 11 प्रतिशत वोट मिले थे। बाकी अन्य छोटे-छोटे दलों का वोट प्रतिशत भी जोड़ लिया जाए तो यह करीब 14 प्रतिशत पहुंचता है। राजनीतिक टीकाकार मानते हैं कि इस बार इस वोट प्रतिशत में कुछ इजाफा हो सकता है। भले ही यह पार्टियां इसे सीट में कन्वर्ट ना कर सकें लेकिन इस चुनाव में उनका मत प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आ सकता है।

एक लाख शव का अंतिम संस्कार करने वाला उतरा चुनावी मैदान में

अब क्या चमकेगी किस्मत या फिर

रामनगर मुक्तिधाम में 32 साल से शंकरलाल साहू अंतिम संस्कार का काम करता आ रहा है। अब वह वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गया है। निगम ने इस ठेका श्रमिक (प्रत्याशी) को चुनाव तक के लिए काम से बैठा दिया है। शंकरलाल का दावा है कि उसने अब तक करीब 1 लाख शव का अंतिम संस्कार किया है। कोरोनाकाल के दौरान उसने अपने परिवार का भी इस कार्य में सहयोग लिया था। उसने कहा कि वह लोगों के साथ ऐसे समय में खडे रहते हैं, जब केवल उनके अपने ही साथ होते हैं। आज वे उस रिश्ते के आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं।

वे इसके पहले महापौर और पार्षद पद के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं। सफलता मिली नहीं, इस बार छत्तीसगढ़ स्वाभिमान पार्टी का प्रत्याशी बनकर मैदान में आए हैं। इस पार्टी को जिला में दुर्ग के पूर्व सांसद ताराचंद साहू ने बनाई थी। जवान फिल्म में किसान की अहम भूमिका निभाने वाले ओंकार दास मानिकपुरी मूल रूप से भिलाई के ही हैं।

उनका जन्म और 5 वीं तक की शिक्षा भिलाई के करीब गांव में हुई है। वे हबीब तनवीर के थिएटर व कंपनी के सदस्य रहे हैं। उनको 21 में आमिर खान की फिल्म पीपली लाइव में कला का जौहर दिखाने का मौका मिला। अब उन्होंने जवान में एक दलित किसान की भूमिका निभाकर सबके मन को जीत लिया है। यह कलाकार रामनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार करने वाले एक व्यक्ति के पक्ष में प्रचार करने आएंगे।

तीन विधानसभा सीटें ऐसी, जहां पासा पलटते देर नहीं लगती

बिलासपुर और मुंगेली जिले की 8 विधानसभा सीटों में 3 ऐसी सीटें हैं जहां हार जीत का पासा पलटते देर नहीं लगती। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में कोटा, बेलतरा और तखतपुर में हार जीत का अंतर 5 हजार तक सीमित रहा है। इसके साथ ही पिछले 4 चुनावों में बिलसपुर, बिल्हा, लोरमी, मस्तूरी, लोरमी और मुंगेली में जीत हार का अंतर 10 के पार रहा है।

प्रदेश में मरवाही ऐसी सीट रही है जहां पिछले 4 विधानसभा चुनावों में जीत का अंतर 35 हजार के पार रहा है। इस बार भी सभी विधानसभाओं में ऐसे ही समीकरण बन रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में बिलासपुर और मुंगेली जिले की 8 सीटों पर मतदाताओं का मन किस करवट बैठता है यह कोई जान नहीं सकता। राज्य स्थापना के बाद से अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में दोनों जिले की 8 विधानसभाओं में आए नतीजे प्रत्याशियों के लिए अप्रत्याशित रहे हैं। नेताजी जीत के प्रति आश्वस्त रहते थे और गिनती के दिन पता चलता था कि उन्हें हार का सामपना करना पड़ा है। जिले के बेलतरा, कोटा और तखतपुर ऐसी सीटें हैं जहां मतदाताओं का मन राष्ट्रीय पार्टी के दोनों प्रत्याशियों के प्रति 50-50 का रहा है। इस बीच दमदार तीसरे प्रत्याशी के चुनाव मैदान में आने से यह स्थिति बिगड़ जाती है। वहीं बिलासपुर, बिल्हा, लोरमी, मस्तूरी और मुंगेली ऐसी विधानसभा सीटें रही हैं जहां जीत हार का अंतर 10 हजार के पार रहा है।

राज्य स्थापना के बाद हुए अब तक के चुनाव में हार जीत का अंतर

विधानसभा क्षेत्र	2003	2008	2013	2018
बेलतरा	299	5000	5000	5000
बिलासपुर	6000	9000	16000	11000
बिल्हा	7000	6000	11000	10000
तखतपुर	7000	5000	608	3000
मुंगेली	7000	10000	5000	9000
लोरमी	15000	5000	6000	25000
कोटा	3000	7000	5000	3000
मस्तूरी	2000	10000	26000	14000

मरवाही एकमात्र ऐसी सीट है जहां प्रदेश की स्थापना के बाद से अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में हार-जीत के अंतर भी पहाड़ से कम नही रहे हैं। वर्ष 2003 में हुए चुनाव में 54 हजार, वर्ष 2008 चुनाव में 42 हजार, वर्ष 2013 चुनाव में 46 हजार और वर्ष 2018 चुनाव में 47 हजार मतों से जीत हार के फैसले हुए हैं। वहीं 2020 में हुए उपचुनाव में भी जीत हार का अंतर 38 हजार वोट थे। यह प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट हैं जहां अब तक सबसे जादा मतों के अंतर से प्रत्याशी जीत दर्ज करते आए हैं।

अब त्योहार के बहाने मतदाताओं को साधने की जुगत में प्रत्याशी...

दिवाली में अब एक का समय शेष हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता त्योहार के बहाने मतदाताओं को साधने की जुगत लगा रहे हैं। इसके लिए घर-घर संपर्क के साथ दिवाली मिलन का आयोजन करने वाली समितियों पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा अपरोक्षरूप से कार्यक्रमों के आयोजन का भी सहारा लिया जा रहा है। इतना ही नहीं इस बार प्रमुख राजनैतिक पार्टियां हाईटेक तरीकों को भी अंजाम रही है। सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल फोन भी लगातार घनघना रहे हैं। फोन उठाते ही घोषणों की बौछार के साथ वोट देने की अपील की जाती है। एक दिन में कई बार फोन आ रहे हैं जिससे लोग भी हलाकान होने लगे हैं।

मतदान 17 नवंबर को है। यह तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक दल व प्रत्याशी हर घर बस्ती और हर मोहल्ले में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत चुनाव से पहले पड़ रहे दिवाली के दौरान आयोजन करने वाली समितियों को भी रिझाने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि चुनाव आचार संहिता और खर्च पर बंदिश के डर से इसे गोपनीय रूप में अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए बकायदा वार्डवार आयोजन समितियों की सूची तैयार की गई है। इस सूची के आधार पर प्रत्याशियों से जुड़े नेता समितियों के पदाधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हर समिति को निश्चित राशि चंदे के रूप में भी पहुंचाई जा रही है। खास बात यह है कि संस्था समितियों के पदाधिकारियों के पास चुनावी मुकाबले में चल रहे नेता एक के बाद एक पहुंच रहे हैं और सहयोग की अपील कर रहे हैं। संगठन के लोग भी मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के लोगों दिन में घर-घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। इस दौरान अलग-अलग समितियों के पदाधिकारियों से छोटी बैठकें भी कर रहे हैं। राजनीतिक दलों द्वारा आमलोगों को रिझाने की जुगत में और भी कार्यक्रम किए जाने की रणनीति तैयार की गई है। इसके लिए राजनैतिक दलों के नेता बूथ स्तर पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दे रहे हैं। बूथ स्तर पर मिलन समारोह की तैयारी कर रहा है। वहीं एन अन्य दल ने समाजों के प्रतिनिधियों को बुलाकर सम्मान समारोह की योजना भी बनाई जा सके।

कोरिया राजपरिवार और भईयालाल फिर आमने-सामने

70 वर्षीय भईयालाल की चुनौती से कांग्रेसियों के होश उड़े

बैकुण्ठपुर वि0स0 क्षेत्र में शुरू से राजपरिवारों का दबदबा रहा है। चुनाव के अपराजेय योद्धा व पूर्व मंत्री स्व0 रामचन्द्र सिंहदेव बैकुण्ठपुर वि0स0 क्षेत्र से 06 बार विधायक रहे वहीं सरगुजा राजपरिवार की पूर्व महारानी स्व0 देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव को भी एक बार बैकुण्ठपुर वि0स0 क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला था । नए परिसीमन के बाद कोरिया राजपरिवार के निशाने पर भाजपा के भईयालाल ही रहे हैं ।

कोरिया राजपरिवार से पराजित हुए भईयालाल कोरिया जिले की राजनीति में उस समय अचानक बदलाव आया जब भाजपा ने नये चेहरे भईयालाल राजवाड़े को चुनाव मैदान में उतारा उनका मुकाबला वर्ष 2003 में कोरिया राजपरिवार के रामचन्द्र सिंहदेव से हुआ था । इस चुनाव में भईयालाल राजवाड़े ने कांग्रेस के परम्परागत रजवार समाज के वोटों में सेंध लगाकर कांग्रेस खेमे में खलबली मचा दी थी । 25-30 हजार मतों से जीतने वाले पूर्व मंत्री रामचन्द्र सिंहदेव की जीत लगभग 5 हजार मतों में सिमट गई थी । इसके बाद ही रामचन्द्र सिंहदेव ने चुनाव की राजनीति से सन्यास लेने की घोषणा कर दी थी । उनका कहना था कि, अब नये चेहरे को जो जनता की सेवा कर सके, सामने आना चाहिए । अम्बिका सिंहदेव ने हराया था भईयालाल को वर्ष 2018 के चुनाव में पहली बार स्व0 रामचन्द्र सिंहदेव की भतीजी अम्बिका

सिंहदेव को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा और लगातार दो बार से भईयालाल से पराजित होती कांग्रेस को संजीवनी मिली। कांग्रेस लहर में लगभग 4 हजार मतों के अन्तर से भईयालाल पराजित हुए । इस चुनाव के पूर्व वर्ष 2008 और 2013 में कोरिया राजपरिवार तो चुनाव मैदान में नही था लेकिन स्व0 रामचन्द्र सिंहदेव द्वारा कांग्रेस से उतारे गए कद्दावर नेता वेदान्ती तिवारी को भईयालाल ने पराजित करने में सफलता पाई थी । वर्ष 2023 में कांग्रेस ने फिर से अंबिका सिंहदेव पर भरोसा जताया ।

भईयालाल के चुनाव प्रचार की आंधी के समक्ष कांग्रेस के हौसले हो रहे पस्त: चुनाव प्रचार में भाजपा की ओर से जहां पूरा संगठन और कार्यकर्ता लगे हुए है कांग्रेस पक्ष में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तुलना में कम सक्रियता कार्यकर्ताओं का

खुलकर चुनाव मैदान में न उतरना जनचर्चा का विषय बना हुआ है । इसके बावजूद कांग्रेसियों के हौसले पस्त नहीं हुए है। बदला चुकाने के लिये बेताब भईयालाल - पिछले चुनाव में हार का बदला लेने के लिए भईयालाल राजवाड़े और उनके साथियों ने पूरी ताकत झोंक दी है । 70 वर्ष के भईयालाल राजवाड़े की चुनौती देखकर कांग्रेसियों के होश उड़ गये है । प्रतिदिन 12-14 घण्टे प्रचार करने वाले भईयालाल को जनता का भरपूर समर्थन भी मिलने का दावा

कर रहे हैं । भईयालाल ने दावा किया है कि 05 वर्ष में अंबिका सिंहदेव के घमण्डी और सख्त आचरण ने आम जनता को ही ने नहीं कांग्रेसियों को भी नाराज कर लिया था । यह नाराजगी इस वि0स0 चुनाव में कोरिया परिवार को बहुत महंगी पड़ने वाली है ।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

मध्यप्रदेश के लिए भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को मध्य प्रदेश चुनाव के लिए घोषणापत्र जारी कर दिया। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्य भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में यह जारी किया गया। बीजेपी के घोषणापत्र में गरीब परिवारों की लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया है। सत्तारूढ़ दल ने गेहूं की खरीद 2,700 रुपये और धान की खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी वादा किया। जेपी नड्डा ने कहा कि समय के साथ साथ घोषणा पत्र की महत्ता धीरे धीरे घटती गई है। क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने और फिर फिर भुलाने का काम किया है। लेकिन भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है, जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपने रोडमैप का जरिया बनाया है और इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चाहे वो मध्य प्रदेश का विकास हो या अन्य किसी प्रदेश के विकास की बात हो, उसके मुल में हमेशा गरीब कल्याण की बात होती है।

कमलनाथ ने निवाड़ी जिला प्रशासन को खुलेआम धमकाया

भोपाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमल नाथ ने शनिवार को एक चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला प्रशासन को धमकाते नजर आए। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि अगले पांच साल के बारे में सोचते हुए कार्रवाई करें। सूत्रों के अनुसार, कमल नाथ निवाड़ी में एक रैली में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी अपने कार्यों के परिणामों से नहीं बच पाएगा, हालांकि उन्होंने आरोपों पर विवरण नहीं दिया। कांग्रेस नेता कमल नाथ ने निवाड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं पृथ्वीपुर और निवाड़ी के प्रशासन से यह कहना चाहता हूं कि आप जो भी कर रहे हैं, उसे ध्यान से सुनें, कल के बाद दिन आएगा और जो करना है वह आप (लोग) और मैं तय करेंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, छह दिन और बचे हैं, जो करना है कर लो, लेकिन अगले पांच साल भी काटने हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे सिसोदिया

नईदिल्ली। मनीष सिसोदिया को शनिवार को सुरक्षा के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई। उन्हें कथित शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को अपनी बीमार पत्नी से मिलने उनके आवास पहुंचे। यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद सिसौदिया को सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दी। अदालत ने उन्हें इस दौरान मीडिया से बात नहीं करने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने का भी आदेश दिया। इससे पहले, सिसौदिया ने पांच दिनों के लिए अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति मांगने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

जयराम रमेश के बयान पर नकवी का पलटवार

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर निशाना साधा। रमेश ने पीएम मोदी पर हमला किया था, जिन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने अभियान के दौरान कांग्रेस पर आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना पीएम मोदी का चरित्र है। रमेश ने कहा था कि चुनाव के समय वह महाझूठ बोलने लगते हैं। जब वह मुख्यमंत्री थे तभी से वह ऐसा कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान वह लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं जैसा कि उन्होंने कल किया था। नकवी ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष को लेकर रमेश पर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र देना कब शुरू किया? उनका अपना चरित्र भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और भ्रम से भरा है।

भाजपा ने येदियुरप्पा के बेटे को बनाया प्रदेश अध्यक्ष

बेंगलुरु। भाजपा द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नेता येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र को कर्नाटक भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त करने पर तीखा पलटवार करते हुए, कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर कटाक्ष किया और उस पर वंशवाद की राजनीति को कायम रखने का आरोप लगाया। शुक्रवार को बीजेपी ने पार्टी लेटरहेड पर विजयेंद्र की पदोन्नति की जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने विधायक विजयेंद्र येदियुरप्पा को कर्नाटक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कर्नाटक में कांग्रेस ने कहा, येदियुरप्पा के बेटे को बधाई, जिन्हें बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। हम राज्य के लोगों से इस झूठ पर विश्वास करने की अपील करते हैं कि भाजपा में कोई परिवारवाद की राजनीति नहीं है।

अमित शाह बोले- कपड़ा फाड़ राजनीति मध्य प्रदेश का नहीं कर सकती भला

कांग्रेस ने हमेशा किया भारतीय संस्कृति का अपमान

भोपाल। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। मध्य प्रदेश के मनावर में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश 3 दीपावली मनाएगा। एक दीपावली कल मनाएंगे, दूसरी 3 दिसंबर को यहां भाजपा सरकार बनने के बाद और तीसरी दीपावली आपको 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मनानी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा भारतीय संस्कृति का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया, महाकाल लोक बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा केदार धाम और मां विंध्यवासिनी के तीर्थ क्षेत्र बनाएं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में मां शारदा पीठ की फिर से पुन: प्रतिष्ठा की और नए संसद भवन में सेंगोल लगाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया।

अमित शाह ने कहा कि एक ओर मोदी जी देश भर के

सभी सांस्कृतिक स्थानों को पुनर्जीवित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस राजा भोज के नाम पर चलने वाली मेट्रो का विरोध करती है, सागर में संत रविदास के मंदिर का विरोध करती है और तो और मां नर्मदा के जयकारे से भी उन्हें तकलीफ है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को कांग्रेस ने यहां अपना नेता बनाया है। लेकिन वो आपके भले के लिए काम नहीं करेंगे। क्योंकि उनके मन में है नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना और सोनिया गांधी जी के मन में है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अपने बेटे-बेटियों के लिए काम करते हैं वो देश और प्रदेश का कभी भला नहीं कर सकते।

भाजपा नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश में 3 परिवार है - कमलनाथ जी का, बंटाधार दिग्विजय जी का, तीसरा है राहुल और सोनिया गांधी का गांधी परिवार। हमारे यहां कहा जाता है कि तीन तिगाडा, काम बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि यहां आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ जी का चलता है और गलती होने पर चांटा दिग्विजय सिंह को लगा देते हैं। ये कपड़ा फाड़ राजनीति मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दलित और आदिवासी विरोधी हैं। ये इतने साल सत्ता में रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी ट्राइबल को राष्ट्रपति नहीं बनाया। मोदी जी ने उड़ीसा की गरीब घर की ट्राइबल बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति बनाकर, देश भर के आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया।

परिवार पहले और राष्ट्र को बाद में पसंद करती है कांग्रेस

गुवाहाटी। असम कांग्रेस के नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के सदस्य पोरीतुश रॉय ने शनिवार को यह कहते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया कि सबसे पुरानी पार्टी केवल नीले खून वाले लोगों का पक्ष ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संबोधित अपने इस्तीफे पत्र में, रॉय, जो असम प्रदेश युवा कांग्रेस (एपीवाईसी) के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस संगठन में बने नहीं रह पाऊंगा। यह केवल नीले रक्त वाले लोगों का पक्ष ले रहा है। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि इस संगठन में हम जैसे लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, जो समाज के निचले तबके से आते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रॉय ने कहा कि कांग्रेस परिवार को पहले और राष्ट्र को बाद में पसंद करती है। उन्होंने कहा कि इस संगठन में काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि, दिसपुर से दिल्ली तक, यह संगठन पहले परिवार और बाद में देश को प्राथमिकता देता है। अत- इस संगठन में काम करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया है और इससे देश की आम जनता के हित खतरे में पड़ जायेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) को एक और झटका देते हुए, असम प्रदेश कांग्रेस के नागांव जिले के अध्यक्ष सुरेश बोरा ने गुरुवार (9 नवंबर) को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बाद में, पोरिटुश रॉय और सुरेश बोरा दोनों शनिवार को एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग भारत और असम के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए वंशवादी और परिवार केंद्रित पार्टियों में कोई जगह नहीं है क्योंकि केवल बीजेपी ही भारत के हित में काम करती है।

भाजपा ने गहलोत सरकार और कांग्रेस को घेरा

नईदिल्ली। दौसा नाबालिग बलात्कार मामले को लेकर भाजपा ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा पर निशाना साधा है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गहलोत सरकार की निष्क्रियता, निकम्मेपन और नाकारापन से भरी हुई सरकार के चलते आज राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत और पूरी मानवता को शर्मसार करने वाला एक कृत्य राजस्थान से सामने आया है। एक दलित परिवार की खुशी छीनने और कुकर्म का विभत्स कार्य गहलोत सरकार की वजह से वहां हुआ है। भाजपा नेता ने अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि जब राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बन जाए तो वहां की महिलाएं जाएं कहां? दौसा में एक 4 साल की दलित बच्ची के साथ राजस्थान पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर बर्बरतापूर्वक बलात्कार का घिनौना और हैवानियत भरा कृत्य करता है। लेकिन राजस्थान सरकार इस पर कार्रवाई करने की बजाय अपराधी के बचाव में लग जाती है। उन्होंने कहा कि दौसा की इस घटना के बाद वहां एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई, जबकि ये पॉक्सो का मामला है। भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के वहां प्रदर्शन करने के बाद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। देश भर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बेटी बचाओ का आंदोलन चलाते हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि राजस्थान की गहलोत सरकार बेटी बचाओ की जगह बलात्कारी बचाव और अपराधी बचाव करती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 15 हजार से ज्यादा बच्चियों के साथ उत्पीड़न और बलात्कार के मामले सामने आए हैं।

देश में आम लोगों के लिए केंद्रित शासन शुरू करने का समय: राहुल

बीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि यह पूरे भारत में आम लोगों के केंद्रित शासन के युग की शुरुआत करने का समय है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में अक्षम है। गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर तेलंगाना में 2020 में आत्महत्या करने वाले एक किसान के परिवार के घर की अपनी हालिया यात्रा का एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो के साथ अपने पोस्ट में, पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने तेलंगाना में पार्टी की गारंटी पर जोर देते हुए कहा कि वे राज्य के लोगों को राहत प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

राहुल गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण आवाज पंक्ति में आखिरी आवाज होती है। कुम्मारी चंद्रय्या की आवाज ऐसी ही एक आवाज थी और दोराला बीआरएस सरकार ने उन्हें विफल कर दिया। वह तेलंगाना के एक छोटे किसान थे, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। उन्होंने अपने प्यारे परिवार को पीछे छोड़कर आत्महत्या कर ली। गांधी ने मृतक किसान के परिवार से मिलने का वीडियो साझा किया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अगर चंद्रय्या को सही समय पर सरकारी सहायता दी गई होती, तो वह अब भी जीवित होते और अपने प्रियजनों के बीच होते। बीआरएस और भाजपा की तरह डोराला की सरकार तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है।

राहुल गांधी ने सवाल किया, क्या कांग्रेस सरकार से कोई फर्क पड़ेगा? उन्होंने इसका जवाब भी दिया और बोले, बिल्कुल, हाँ! उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस की गारंटी करोड़ों ऐसी आवाजों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है, जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा, हमारी गारंटी तेलंगाना में

हमारे लोगों को न्यूनतम मंजिल प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। कुम्मारी तिरुपथम्मा ने मुझे बताया कि उनका परिवार ऋण के बोझ तले संघर्ष कर रहा है। यह बहुत जल्द बदल जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की प्रजला सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह महालक्ष्मी प्रदान करेगी। महिलाओं को नि:शुल्क बस यात्रा; और 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 15,000 रुपये प्रति वर्ष रायथु भरोसा देने का भी वादा किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि कृषि मजदूरों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा।

उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई अब अपने सभी लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की है। यह पूरे भारत में जन-केंद्रित शासन के युग की शुरुआत करने का समय है। वीडियो में, राहुल गांधी पीड़ित परिवार की समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक स्थानीय कांग्रेस नेता को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दे रहे हैं कि परिवार की भूमि की मिट्टी का परीक्षण किया जाए और स्वामित्व मृतक किसान की विधवा को हस्तांतरित किया जाए, जिसने आत्महत्या कर ली थी।कांग्रेस तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने की कोशिश कर रही है।

खेल
प्रमुख समाचार

राहुल द्रविड़ ने की रोहित शर्मा की जमकर तारीफ

नईदिल्ली। मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने शनिवार को यहां स्वीकार किया कि विश्व कप में भारत की आठ मैच की जीत की लय में रोहित शर्मा का टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज के तौर पर शानदार तरीके से दोहरी भूमिका में ढलने का अहम हाथ रहा है।

रोहित ने शानदार ढंग से भारतीय टीम का नेतृत्व करने के अलावा बतौर सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को आक्रामक शुरूआत भी करायी है। बल्कि उन्होंने आठ मैचों में 122 के स्ट्राइक रेट से 443 रन बनयो हैं।

द्रविड़ ने नीदरलैंड के खिलाफ भारत के अंतिम लीग मैच की पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''रोहित निश्चित रूप से एक लीडर रहा है।मुझे लगता है कि उसने मैदान के अंदर और बाहर दोनों में उदाहरण पेश किया है। ''उन्होंने कहा, ''ऐसे भी कुछ मैच रहे हैं जो हमारे लिए पेचीदा हो सकते थे लेकिन वह सच यही है कि वह हमें उस तरह की शुरूआत दिलाने में सफल रहे हैं जिससे मैच हमारे लिए अच्छा रहा है। ''

उन्होंने कहा, ''वास्तव में इससे मैच हमारे लिए आसान दिखता है और निश्चित रूप से यह उन खिलाड़ियों के लिए भी आसान हो गया जो बल्लेबाजी विभाग में उनके बाद उतरे। '' द्रविड़ ने कहा कि रोहित ने टीम के जरूरतों के अनुसार खेलकर दूसरों के सामने उदाहरण पेश किया है और इससे भारतीय ड्रेसिंग रूम में काफी बड़ा असर पड़ा है। रोहित ने इस विश्व कप में अब तक जिस आक्रामकता से पारी का आगाज किया है, वह अन्य के लिए प्रेरणा का काम करता रहा है। द्रविड़ ने कहा, ''हम एक विशेष तरीके से खेलने के बारे में बात करते हैं। आप ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका नेतृत्व करने वाला ऐसा नहीं करता और आपके सामने उदाहरण पेश नहीं करता। रोहित ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह शानदार है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

बीएसई का दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ चार गुना बढ़ा

नईदिल्ली। शेयर बाजार बीएसई का चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ चार गुना होकर 118 करोड़ रुपये हो गया। शेयर बाजार ने एक बयान में यह जानकारी दी। बीएसई का बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में शुद्ध लाभ 29.4 करोड़ रुपये रहा था। बीएसई ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में एक्सचेंज का राजस्व 53 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 367 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 240 करोड़ रुपये था। बीएसई के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सुंदरमन राममूर्ति ने कहा, हम मानव संसाधनों, नए उत्पादों, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे आदि के विकास में निवेश करना जारी रखेंगे, और इस प्रकार दीर्घकालिक विकास शेयरधारकों को आगे बढ़ाएंगे और वाइब्रेंट बीएसई 2025 के अपने मिशन को पूरा करेंगे।

धनतेरस पर वाहन, उपभोक्ता सामानों की बिक्री में उछाल

नईदिल्ली। धनतेरस के दौरान बाजार में रौनक रही और वाहन विनिर्माताओं, उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों और उपकरण विनिर्माताओं ने अच्छी बिक्री दर्ज की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह प्रवृत्ति अगले तीन दिन तक जारी रहेगी। विनिर्माताओं ने आकर्षक ऑफर और योजनाओं के कारण पिछले साल की समान अवधि की तुलना में दीपावली से पहले धनतेरस की बिक्री के दौरान दहाई अंक में उच्च वृद्धि दर्ज की है। मारुति सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव के अनुसार, धनतेरस पर यात्री वाहन उद्योग की थोक बिक्री 21 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है। देश की दूसरी अग्रणी वाहन निर्माता हुंदै मोटर इंडिया लिमिटेड (एचएमआईएल) ने थोक बिक्री में पिछले साल की तुलना में दो गुना वृद्धि की है।

टाटा केमिकल्स का शुद्ध लाभ 28% घटकर 495 करोड़ रुपये

नईदिल्ली। टाटा केमिकल्स लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 28 प्रतिशत घटकर 495 करोड़ रुपये रहा। कंपनी को एक साल पहले इसी तिमाही में 685 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। कंपनी की परिचालन से होने वाली आय जुलाई-सितंबर तिमाही में घटकर 3,998 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में यह 4,239 करोड़ रुपये थी। टाटा केमिकल्स ने शुक्रवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ''समीक्षाधीन तिमाही के दौरान एकीकृत आधार पर शुद्ध लाभ 495 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही में यह 685 करोड़ रुपये था।''

गूगल का एआई में करोड़ों डॉलर के निवेश का प्लान

नईदिल्ली। गूगल अब एआई की दुनिया में भी अपने पैर मजबूत करने की तैयारी में हैं। हाल ही में आई खबर के अनुसार, गूगल चैटबोट स्टार्टअप कैरेक्टर एआई में करोड़ों डॉलर का निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। ये स्टार्अप, मॉडल्स को प्रशिक्षित करने और यूजर्स की मांग को पूरा करने के लिए पूंजी जुटाना चाहता है। इस बारे में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस निवेश के लिए गूगल कन्वर्टिबल नोट्स के रूप में स्ट्रक्चर तैयार करने कर सकता है। बता दें, कैरेक्टर एआई की पहले से ही गूगल के साथ मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए गूगल की क्लाउड सर्विसेज और टेन्सर प्रोसेसिंग यूनिट्स (टीपीयू) का इस्तेमाल करता है। अगर अब गूगल इसमें नया निवेश करता है तो इससे दोनो के बीच मौजूदा साझेदारी और गहरी हो जाएगी।

भारत-यूके व्यापार समझौता संभावनाएं और चुनौतियां

अजय श्रीवास्तव

भारत दिसंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जनवरी 2022 में दोनों देशों ने व्यापक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए तेज गति से बातचीत शुरू की। फिलहाल वह बातचीत संपन्न होने के निकट है और दोनों देशों की टीमें कुछ आखिरी मुद्दों को हल करने में लगी हैं। इस वर्ष के अंत तक एफटीए पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।

दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत अधिक नहीं है और 2022-23 में इसने 44.3 अरब डॉलर का स्तर पार किया। भारत 25.8 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है और उसका व्यापार अधिशेष 8 अरब डॉलर का है।

यह आंकड़ा यूनाइटेड किंगडम सरकार के कारोबार और व्यापार विभाग से प्राप्त हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्विपक्षीय सेवा व्यापार के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करता। ऐसे में दोनों देशों के मुक्त व्यापार समझौते से क्या उम्मीद की जा सकती है? मुक्त व्यापार समझौते में 26 विषयों पर बातचीत शामिल है जिनमें वस्तु एवं सेवा व्यापार, टिकाऊपन, बौद्धिक संपदा अधिकार और श्रम संबंधी मसले शामिल हैं। इन विषयों के मुताबिक वार्ताकार भारत के बढ़ते डिजिटल और उपभोक्ता बाजार का लाभ लेने के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम की उन्नत तकनीक तथा वित्तीय क्षेत्रों पर ध्यान देंगे जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। अनिवार्य तौर पर देखें तो मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार और आर्थिक पूरकता का लाभ लिया जाना चाहिए। इसमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी? आइए देखते हैं कि प्रमुख विषयों

को लेकर क्या बाधाएं होंगी, किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा और क्या नतीजे हासिल हो सकते हैं।

वाणिज्यिक व्यापार- भारतीय स्मार्ट फोन, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाएं, हीरे, मशीनों के कलपुर्जे, विमान और लकड़ी के फर्नीचर इस समय यूनाइटेड किंगडम के बाजारों में शुल्क मुक्त हैं। इन उत्पादों का कुल मूल्य 6 अरब डॉलर है यानी वित्त वर्ष 2023 में भारत के वस्तु निर्यात का आधा। पहले से ही शुल्क मुक्त घोषित इस निर्यात में मुक्त व्यापार समझौते से मदद नहीं मिलेगी। इसके विपरीत भारत का कपड़ा और वस्त्र, जूते-चप्पल, कालीन, कार, समुद्री उत्पादों तथा कुछ तरह के फलों का निर्यात करीब 5 अरब डॉलर मूल्य का है और इस पर यूनाइटेड किंगडम में चार से 16 फीसदी कर लगता है। इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते से अवश्य लाभ होगा। बहरहाल, अहम वृद्धि हासिल करने के लिए उत्पाद गुणवत्ता में सुधार करना होगा क्योंकि हमारा लक्ष्य एक विकसित बाजार है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 47,400 डॉलर है और ग्राहक भी संपन्न हैं।

फिलहाल यूनाइटेड किंगडम के 90 फीसदी से अधिक उत्पादों को भारत में उच्च टैरिफ का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम से भारत को होने वाला सबसे बड़ा निर्यात चांदी है जो वित्त वर्ष 2023 में 2.7 अरब डॉलर रहा। इस पर फिलहाल 12.5 फीसदी शुल्क लगता है। अन्य भारतीय शुल्कों की बात करें तो कारों पर 100 से 125 फीसदी और स्कॉच व्हिस्की पर 150 फीसदी कर लगता है। यूनाइटेड किंगडम के उत्पादों पर औसत भारतीय शुल्क 14.6 फीसदी है। भारत भी ऑस्ट्रेलिया के समान कई उत्पादों को रियायत दे सकता है तथा यूनाइटेड किंगडम के वाहनों तथा स्कॉच व्हिस्की पर शुल्क कम कर सकता है। 2023 में यूनाइटेड किंगडम ने भारत में 1.50 अरब डॉलर मूल्य के एल्युमीनियम, लोहा, तांबा और कागज की रद्दी की आपूर्ति की। स्रोत से संबंधित नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि तीसरे देश के उत्पादों को मुक्त व्यापार समझौते का लाभ केवल तब मिले जब मुक्त व्यापार समझौते के साझेदार देश में उसका महत्त्वपूर्ण प्रसंस्करण हुआ हो। चांदी यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ी निर्यात वस्तु है और भारत के लिए इसलिए चुनौती उत्पन्न हुई क्योंकि यूनाइटेड किंगडम प्राथमिक तौर पर आयातित चांदी का प्रसंस्करण करके उसे दोबारा निर्यात करता है। वह इस दौरान अधिक मूल्यवर्द्धन नहीं करता।

छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर के बाद तेज हो सकती है ईडी की कार्रवाई

माना जा रहा है कि 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान निपटने के बाद छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई तेज हो सकती है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता भी ईडी के लपेटे में आ सकते हैं। इसके अलावा दो विधायकों पर भी सख्ती हो सकती है। ये विधायक पहले से ही ईडी के टारगेट में है। चर्चा है कि ईडी दोनों को गिरफ्तार कर सकती है। महादेव ऐप मामले में भी ईडी जांच का दायरा बढ़ा सकती है। कहते हैं कि चुनाव के चलते ईडी कार्रवाई धीमी कर दी थी। ईडी की जाल से बचने के लिए एक कांग्रेस नेता लंबे समय से गायब हैं। खबर है कि ईडी उन्हें भी गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाने वाली है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।

चुनाव में चांदी काटते कलेक्टर

कहते हैं चुनाव के मौसम में राज्य के कुछ कलेक्टरों की दसों अँगुलिया घी में डूबी हुई है। चर्चा है कि चुनाव के नाम पर कलेक्टर किसी की भी गाड़ी अटैच कर ले रहे हैं तो ऑब्जर्वर के सेवा सत्कार के नाम पर दिवाली मना रहे हैं। कहते हैं कि कुछ कलेक्टर महोदय ऑब्जर्वर की सेवा सत्कार में अपने जिलों के मलाईदार विभागों के अफसरों की ड्यूटी लगा रखे हैं। वे इन विभागों के अफसरों से ऑब्जर्वर को महंगे होटल में रुकवा रहे हैं तो दिवाली के महंगे गिफ्ट दिलवा रहे हैं और अपने लिए भी गिफ्ट बुलवा रहे हैं। एक आदिवासी बहुल जिले के कलेक्टर साहब ने तो चुनावी मौसम में अपने लिए घरेलू सामान खरीदवा लिए। चुनाव के समय आयोग का डंडा चलता है। अब आयोग के प्रतिनिधि को कौन क्या कहे ?

आईपीएस ईडी के निशाने में

ईडी ने महादेव ऐप मामले में दो आईपीएस अफसरों को तलब कर उनसे पूछताछ कर चुकी है। चर्चा है कि कुछ और आईपीएस अफसर ईडी की जद में आ सकते हैं। इनमें कुछ आईजी स्तर के तो कुछ एसपी स्तर के अफसर हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि ईडी महादेव ऐप से जिन पुलिस अफसरों के तार जुड़े हैं, उन्हें जल्द नोटिस जारी कर सकती है। माना जा रहा है कि 17 नवंबर के बाद ईडी का एक्शन तेज हो सकता है। वैसे छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप की गुत्थी उलझते ही जा रही है और इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। महादेव ऐप विधानसभा चुनाव में भी खूब उछल रहा है।

चुनाव के केंद्र में ढेबर बंधु

रायपुर दक्षिण के भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के साथ पिछले दिनों घटित घटना के बाद ढेबर बंधु चुनाव के केंद्र में आ गए हैं। खासतौर से महापौर एजाज ढेबर ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। यहाँ से महंत रामसुन्दर दास कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पर घटना के बाद भाजपा ने ढेबर बंधु को निशाने पर ले लिया है। कहा जा रहा है कि बैजनाथपारा की घटना के पहले माहौल कुछ और था। घटना के बाद माहौल कुछ और हो गया है। इस घटना के बाद कहा जाने लगा है कि भाजपा ने नहले पर दहला चल दिया।

पहले चरण के मतदान के बाद हवा में कांग्रेस -भाजपा

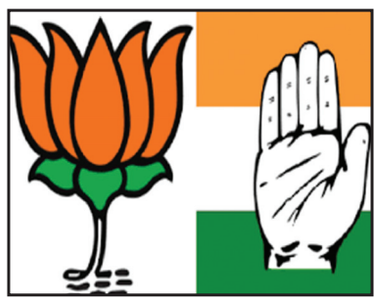

कहते हैं छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से खुलता है। बस्तर में मतदान हो चुका है। बस्तर इलाके के साथ राजनांदगांव और कवर्धा जिले में भी वोटिंग हो चुकी है, इसके बाद राजनीतिक दल अपने-अपने तरह से जीत का आंकलन कर रहे हैं। कांग्रेस पहले चरण के 20 सीटों में जीत का दावा कर रही है तो भाजपा भी पीछे नहीं है,वह भी 15-16 सीटों पर जीत की बात कर रही है । लोग अनुमान लगा रहे हैं कि पहले चरण के मतदान वाले इलाकों में 2018 जैसा पिक्चर नहीं रहने वाला है। पहले चरण के मतदान वाले इलाकों में मुकाबला साफ़ तौर से भाजपा और कांग्रेस में ही दिखाई दे रहा है।

अमित जोगी के वजूद का सवाल

कहा जा रहा है अमित जोगी अपने पिता अजीत जोगी से दो कदम आगे चल रहे हैं। अजीत जोगी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का ताल ठोंका था , पर लड़े नहीं। अमित जोगी ने कछुआ चाल चलते वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन में मैदान में उतर गए हैं। 2018 में अजीत जोगी ने सड़क मार्ग से चुनाव प्रचार किया था,पर 2023 में अमित जोगी हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। जोगी कांग्रेस ने 81 प्रत्याशी खड़े किए हैं, उनमें से कितने लोग जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं , उससे अमित जोगी का वजूद तय होगा।

भाजपा नेता की अमित शाह से शिकायत

कहते हैं भाजपा के एक प्रत्याशी ने अपने एक वरिष्ठ नेता की पिछले दिनों अमित शाह से शिकायत की और उसे हराने के लिए बागी प्रत्याशी खड़े करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रत्याशी को अमित शाह का विश्वस्त माना जाता है। कहा जाता है प्रत्याशी और भाजपा नेता की लड़ाई पुरानी है, पर इन दिनों प्रत्याशी को अमित शाह का आशीर्वाद मिलने से भाजपा के कुछ नेता परेशान हैं और उन्हें दबाने में लग गए हैं। माना जा रहा है कि प्रत्याशी चुनाव जीत गया तो आने वाले दिनों में भाजपा के कई दिग्गजों के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। इस कारण प्रत्याशी को चुनाव हराने की जुगत चल रही है।

तेल और तेल की धार देखने में लगे अफसर

इन दिनों राज्य के आला अफसर तेल देखो, तेल की धार देखो की तर्ज पर चल रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे के मुकाबले की बात हो रही है। ऐसे में किसकी सरकार बनेगी, उसका आंकलन कोई नहीं कर पा रहा है। दोनों दल किसानों, मजदूरों और महिलाओं को लुभाने वाले घोषणा पत्र जारी कर देने से चुनाव काफी रोचक लग रहा है। इस कारण ऊंट किस करवट बैठेगा, कोई कुछ नहीं कह पा रहा है। इस कारण आला अफसर समय के इंतजार में हैं।

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

अकबर क्या जानें महतारी वंदन: साव

■ भाजपा सरकार देगी 50 हजार करोड़, यह मोदी की गारंटी है

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मंत्री मोहम्मद अकबर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अकबर और उनकी कांग्रेस सरकार महतारी वंदन क्या जानें? अकबर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई महतारी वंदन योजना संचालित नहीं है। भाजपा फार्म भरवाकर भ्रमित कर रही है। हमारा कहना है कि कांग्रेस ने महतारी वंदन तो किया नहीं। वह तो महिलाओं का शोषण करने में भरोसा करती है। महतारी वंदन योजना तो हम संचालित करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर हर विवाहित महिला को माह में एक हजार, यानी साल में 12 हजार मतलब 5 साल में 60 हजार रुपये देंगे। यह भाजपा का संकल्प है। मोदी जी की गारंटी है। भाजपा अपनी महतारी वंदन योजना लेकर छत्तीसगढ़ की महतारी, बहनों, बेटियों, बहुओं तक जा रही है तो कांग्रेस और खास तौर पर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के संयोजक अकबर को कष्ट हो रहा है। उनका हाजमा बिगड़ गया है। जब भी महिलाओं के सम्मान, महतारी वंदन की बात आती है तो कांग्रेस को कोफ्त होती है। समझ में नहीं आता कि जननी की वंदना से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है। पहले भी कांग्रेस सिर्फ एक ही महतारी का वंदन करना जानती थी। आज भी वह एक ही महतारी का वंदन कर रही है। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की हर महतारी का वंदन करने 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान करेगी।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने महिलाओं से शराबबंदी, पेंशन, मुफ्त गैस सिलेंडर, स्व सहायता समूह के कर्ज माफ जैसे वादे किए और महिलाओं के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महतारी का अपमान करने का संकल्प ले रखा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेसी बेरोजगार युवाओं से जैसे फॉर्म भरवा रहे थे और बाद में ठेंगा दिखा दिया, ऐसी भाजपा की संस्कृति नहीं है।

झूमाझटकी मामले में सीएम के बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन का पलटवार, बोले-

करूंगा मानहानि का मुक़दमा, निर्वाचन आयोग में शिकायत भी

रायपुर। पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, जो घटना घटित हुई उस घटना के बाद सीएम की प्रतिक्रिया से आहत और दुखी हूं. उनके शब्द बेहद आपत्तिजनक हैं. सीएम को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. 7 बार रायपुर की जनता ने चुना है. सीएम की कृपा से मैं मंत्री नहीं था. जिन शब्दों का उपयोग हुआ है किसी को ऐसे शब्द नहीं उपयोग करना चाहिए. अग्रवाल ने कहा, मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा और निर्वाचन आयोग में भी शिकायत दर्ज करूंगा. मेरा उनको चैलेंज है कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, सीट का निर्णय वह करेंगे, मैं ताल ठोक रहा हूं वह भी ताल ठोकें.

प्रेस कांफ्रेंस में सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, सीएम पैसा खोर हो गए हैं. जो छत्तीसगढ़ को लूट रहे हैं उन्हें नजदीकी बनाकर क्या फायदा. आपने छत्तीसगढ़ को अपराधियों के

हवाले सौंप दिया है क्या..? रायपुर मेरा घर है. मेरा सबसे अच्छे संबंध हैं. रायपुर में कोई नहीं कह सकता कि मैने किसी के साथ भेद भाव किया हो. कांग्रेस अब माफियाओं के संरक्षक हो चुके हैं. चुनाव भी ठेके पर दिए जाते हैं, यह पहली बार सुन रहा हूं. हमारे लोगों को धमकी दी जाती है. 14 नवंबर को खुलासा करूंगा की किसे धमकी दी गई है.

उन्होंने कहा, जब कहा जाता है कि मैं बृजमोहन का कार्यकर्ता हूं तब उन्हें कहा जाता है कि 17 नवंबर के बाद देख लूंगा. बैजनाथ पारा में हमारी गाड़ी रोक दी जाती है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता. या तो रायपुर की पुलिस नपुंसक हो गई है या बिक गई है. महादेव एप सट्टा के भागीदारों के साथ भागीदार बन गई है. पुलिस को चेतावनी देता हूं, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता को धमकाया जाता है या तो पुलिस कार्रवाई करें या फिर हम इन गुर्गों को घर से निकालकर बताएंगे. छत्तीसगढ़ में उन्हें हार दिखाई दे रही है. हमारी संख्या ज्यादा थी इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई.

मैने संयम से काम लिया. हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहार पर किसी भी प्रकार की घटना और अशांति हो इसलिए मैं नहीं चाहता. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा और निर्वाचन आयोग में भी शिकायत दर्ज करूंगा. मेरा उनको चैलेंज है कि मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, सीट का निर्णय वह करेंगे, अगर दम है तो मैं ताल ठोक रहा हूं वह भी ताल ठोकें.बृजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया बाकी आरोपियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया. महापौर के वार्ड में ऐसा क्यों..? मैं मुख्यमंत्री से जवाब चाहता हूं. मुख्यमंत्री जी आप अपने वरिष्ठ विधायक साथी के खिलाफ जो अपशब्दों का उपयोग किया उसके लिए आपको शर्मिंदगी है.

केन्द्रीय मंत्री ठाकुर ने पार्टी के लिए मांगे वोट

बलरामपुर। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री शांतनु ठाकुर बलरामपुर जिले के रामानुजगंज धनगांव में बीजेपी उम्मीदवार रामविचार नेताम के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान बंगाली मतुआ समुदाय के लोगों से बीजेपी को वोट देकर जीताने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को मिलेगा। रामानुजगंज विधानसभा सीट पर बंगाली समुदाय के मतदाता बड़ी संख्या में हैं। इस सीट पर जीत हार में बंगाली समुदाय की निर्णायक भूमिका रहती है। इसलिए बीजेपी ने यहां बंगाली मतुआ समुदाय को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रामानुजगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी-कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। बंगाली समुदाय के मतदाताओं के बीच प्रभावशाली सामाजिक धार्मिक संप्रदाय ठाकुरबाड़ी के उत्तराधिकारी हैं। वह मतुआ समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेता हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

भाजपा की नीतियां सदैव जनहित में होती है: पुरंदर

रायपुर। भाजपा प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने कहा, भाजपा की नीतियां सदैव जनहित के ही उद्देश्य से बनाई जाती हैं, लेकिन विपक्षी दलों के लोग हमेशा नीतियों के क्रियान्वयन में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्र नरेंद्र मोदी ने जनहित से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव हर जगह देखने मिल रहा है। वहीं सिंधी समाज से मिल रहा जनसमर्थन यह संदेश दे रहा है कि इस पोलिंग बूथ से सर्वाधिक वोटों के साथ लीड दिलाएंगे। श्री मिश्रा का जगह-जगह महिलाओं ने पूजा की, आरती सजाकर स्वागत किया। इसके अलावा महिला समिति के द्वारा पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। ऐसे जनसमर्थन से अभिभूत पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जनता के स्नेह और आशीर्वाद से चुनाव में जीत के प्रति वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भाजपा प्रत्याशी श्री मिश्रा ने भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भाजपा मंडल तेलीबांधा चुनाव कार्यालय के नजदीक राजधानी चेंबर से दौरा और जनसंपर्क की शुरुआत की। वे श्याम नगर गुरुद्वारा रोड से बाबा नामदेव के दरबार पहुंचे और मत्था टेकने के बाद जनसंपर्क शुरु किया। इसी तरह मदर टेरसा वार्ड के श्याम नगर सिंधी कालोनी में गली नंबर 7 से लेकर 1 तक डोर टू डोर मतदाताओं से भाजपा को जीताने के लिए आशीर्वाद मांगा।

दक्षिण विस से बृजमोहन अग्रवाल की विदाई सुनिश्चित: ठाकुर

रायपुर। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ियाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बृजमोहन अग्रवाल का अनर्गल अभद्र टिप्पणी करना हार की बौखलाहट है। रायपुर दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल की विदाई सुनिश्चित हो गई है। बृजमोहन अग्रवाल को अपनी करारी हार के संकेत मिलने से अब हिन्दू-मुस्लिम फसाद कराने का षड्यंत्र रच रहे है, जिसकी पोल वीडियो में खुल गया। भाजपाई शहर की शांत फिजा में नफरत का जहर घोल रहे है। बृजमोहन अग्रवाल की करतूत की निंदा पूरे शहर में हो रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्री रहते डॉलर में घूस लेने वाले बृजमोहन चुनाव हारते देख कर बौखला गये है। उन्हें पता है कि विधायक नहीं रहेंगे तो झलकी की किसानों की जमीन वापस करने की नौबत आ जायेगी। इसीलिये अनर्गल बयानबाजी और झूठे हमले की कहानी गढ़ रहे है। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल की दबंगई एकात्म परिसर में दिखा था। सन 2000 में नेता प्रतिपक्ष चुनाव हेतु पर्यवेक्षक बनकर आये नरेंद्र मोदी को भी टेबल के नीचे छिपकर अपनी सुरक्षा करनी पड़ी थी। बृजमोहन अग्रवाल के पैसा का अहंकार इस बार दक्षिण की जनता तोड़ेगी।15 साल के सत्ता के दौरान अकूत काली कमाई बृजमोहन अग्रवाल ने किया था। सरकारी जमीनों पर कब्जा करना सड़क पर कब्जा करना उनके परिजनों का काम था।

ईडी ने सीएम की छवि खराब करने रचा षड़यंत्र: शुक्ला

रायपुर। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि ईडी ने कुछ दिनों एक ड्राइवर को पकड़ा था, जिसके कथित बयान के आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव एप्प से 508 करोड़ रू. लेने का आरोप लगाते हुये एक प्रेस नोट जारी किया था।ईडी के प्रेसनोट का आधार ड्राइवर असीम दत्ता का कथित बयान था जिसका की दावा ईडी कर रही है लेकिन उसी असीम दत्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो बयान दिया है उससे इस मामले में ईडी और षड़यंत्र पूरी तरह से खुल कर सामने आया है। ईडी का यह प्रेस नोट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा था तथा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के लिये किया गया षड़यंत्र था। भाजपा की केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि खराब करने के उद्देश्य से एक दुर्भावनापूर्वक प्रेस नोट जारी किया। इसमें ईडी ने सिर्फ एक आरोपी के फौरी बयान के आधार पर मुख्यमंत्री के खिलाफ बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जांच के पैसे लेने का प्रेसनोट हड़बड़ी में जारी कर दिया। ईडी के द्वारा जारी प्रेसनोट यह साबित करने के लिये पर्याप्त है कि यह भाजपा को एक चुनावी मुद्दा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की छवि खराब करने के उद्देश्य से षड़यंत्रपूर्वक जारी किया है।

कांग्रेस जो कहती है वह करती है : मो. अकबर

रायपुर। मंत्री मो. अकबर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन ने राजीव भवन में पत्रकारवार्ता को संबोधित किया। मंत्री मो. अकबर ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव चल रहा है। 20 विधानसभा में चुनाव हो चुके है। बाकी विधानसभा के चुनाव के लिये 17 नवंबर मतदान किया जायेगा। कांग्रेस पार्टी ने 2018 में घोषणा पत्र के जरिये 68 विधानसभा सीटों में जीत हासिल हुआ। उन घोषणा पत्र में जो वायदा किया गया था उनमें से अधिकांश वायदे कांग्रेस पार्टी ने पूरा करने में सफल रही। जिसमें किसान को कर्जा माफ, सभी को राशन कार्ड देने की बात कही गयी थी और किसानों को 2500 रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की बात कही गयी थी और इसके अलावा और भी प्रमुख वायदे थे। लेकिन प्रमुख तौर पर इन वायदो को फोकस किया गया था। कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ किया गया और पूरे राज्य में वायदो के मुताबिक राशन कार्ड दिया गया। भाजपा सरकार की में पहले गरीबी रेखा में जिनका नाम था उनको ही राशन कार्ड दिया जाता था और कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी को राशन कार्ड बनाकर दिया गया। 74 लाख 54 हजार लोगों के पास राशन कार्ड है। कांग्रेस ने 2018 में जो किसानों का कर्जा माफ हुआ उसी तरह 2023 में कांग्रेस की सरकार बनते ही फिर से किसानों का कर्जा माफ किया जायेगा। धान का मूल्य न्याय योजना को मिलकार 3200 रू. प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जायेगा।

वादों को चुनाव के बाद जूमला बताने वाली भाजपा का क्या भरोसा : विकास उपाध्याय

रायपुर। जनवंदन यात्रा में लोगों से जनसंपर्क कर रहे विकास उपाध्याय को जनता ने भरपूर आशीर्वाद के साथ हरसंभव मदद करने आश्वासन दिया है। शनिवार को श्री उपाध्याय आम जनता से मिलने रामनगर, सरोना, पार्थिव नगर, इन्द्रप्रस्थ फेस-2, मीरा नगर व देवनगरी पहुँचे, जहाँ उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके अलावा उन्होंने साहू समाज, ब्राह्मण समाज व बोहरा समाज की बैठक लेकर अपनी बात रखी और सहयोग मांगा। वे टाटीबंध में व्यापारियों से भी मिले, साथ ही ड्राईवर यूनियन के लोगों से भी भेंट की। श्री उपाध्याय ने कहा कि भाजपा को जनता अच्छी तरह समझती है कि वह झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद अपनी ही बातों को जूमला बताती है, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए वादे कर दिये हैं और गारंटी फार्म भरा रही है लेकिन आखिर में होगा क्या? कुछ नहीं, फिर जनता छली जाएगी। कालाधन, 15-15 लाख, प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आज तक पूरी नहीं हो पायी, ऐसे ही उनके अभी विधानसभा चुनाव में किये गए वादे भी पूरे नहीं होंगे। श्री उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में जो वादे किये थे उसे पूरा किया, 2023 में फिर जनता के बीच अपने किये काम और नये वादों के साथ हैं, जिसे फिर पूरा करेगी।

ऐसा है टीएस बाबा का साम्राज्य

428 करोड़ की गैर खेतिहर जमीन, राजमहल से मर्सिडीज-पेट्रोल पंप तक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले राज्य में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है जिसमें कई बड़े चेहरों ने भी अपना पर्चा भरा है। इन चेहरों में राज्य के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव बाबा भी शामिल हैं। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है।

उपमुख्यमंत्री के हलफनामे से कई जानकारियां सामने आई हैं। शपथ पत्र के मुताबिक, पिछले पांच साल में उनकी संपत्ति में कमी हुई है। करोड़ों के मालिक उपमुख्यमंत्री के पास कई वाहन हैं।

उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल 447 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई है। 2018 के चुनाव में उन्होंने कुल 500 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति बताई थी। 2013 में सिंहदेव के पास कुल 561 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। इस तरह बीते 10 साल में उनकी संपत्ति में 114 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमी आई है।

कमाई की बात करें तो 2018-19 में उपमुख्यमंत्री की कुल कमाई 2.01 करोड़ रुपये थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में काफी कमी आई। 2019-20 में ये घटकर 63.57 लाख रुपये हो गई। 2020-21 में टीएस सिंहदेव की कमाई में फिर कमी आई और ये

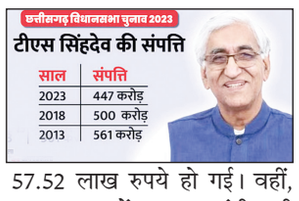

57.52 लाख रुपये हो गई। वहीं, 2021-22 में उपमुख्यमंत्री की कमाई में बढ़ोतरी हुई और ये बढ़कर 61.70 लाख रुपये हो गई। शपथ पत्र के मुताबिक, 2022-23 की कमाई फाइल नहीं की गई है।

शपथ पत्र में उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी कि इस वक्त उनके पास 1.70 लाख रुपये ही नकद हैं। टीएस सिंहदेव के 25 बैंक खातों में 2.24 करोड़ रुपये जमा हैं।

टीएस बाबा के 46.75 लाख रुपये के चार कंपनियों और निधियों में शेयर हैं। इसी तरह उनके 17 लाख रुपये की दो बीमा जमा की हुई हैं। उपमुख्यमंत्री को 5.05 करोड़ रुपये 33 व्यक्तियों और निकायों को दिए ऋण और एडवांस से मिले हैं। टीएस सिंहदेव अपने पास 4.11 करोड़ रुपये मूल्य के गहने रखे हुए हैं। वहीं, पत्नी निधि के पास 5.26 करोड़ रुपये के जेवरात हैं।

उपमुख्यमंत्री टीएस बाबा के हलफनामे के अनुसार, उनके नाम पर 53.42 लाख रुपये कीमत के कुल पांच कारें हैं। टीएस के पास 40 लाख रुपये की सबसे महंगी कार मर्सिडीज है। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री के पास एक लाख रुपये की होंडा सिविक कार, आठ लाख रुपये की महिंद्रा एक्सयूवी, 1.87 लाख रुपये की वरना कार और 1.50 लाख रुपये की होंडा कार हैं।

कांग्रेस नेता अपने पास 1.04 करोड़ रुपये मूल्य के गहने रखे हुए हैं जिनमें सोने, चांदी, हीरे और मोती से जड़े आभूषण भी शामिल हैं।

उपमुख्यमंत्री अपने पास 22 बोर की राइफल और 12 बोर की रिवॉल्वर भी रखते हैं जिनकी कीमत उन्होंने 1.5 लाख रुपये बताई है। इस प्रकार से उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव कुल 10.99 करोड़ रुपये की चल संपत्ति के मालिक हैं।

चुनाव को लेकर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने पुलिस अधिकारियों की ली बैठक

■ कानून व्यवस्था और आचार संहिता के पालन कराने दिये आवश्यक निर्देश

रायपुर। विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के लिए 17 नवम्बर को चुनाव होने वाला है. चुनाव को लेकर रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी थाना प्रभारी और जिले में चुनाव के लिए आये अर्धसैनिक बल के अधिकारियों की बैठक ली. एसएसपी ने शराब या अन्य वस्तु बांटकर चुनाव को कोई प्रभावित ना करे इसके लिए सतर्क और सजग रहकर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया.

प्रत्याशियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने और प्रचार के दौरान कोई अप्रिय स्थिति ना हो इसके लिए सजग रहने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी को निर्देशित किया. साथ ही चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन और चुनाव संबंधित अन्य शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई करते हुए विधिसम्मत निराकरण किये जाने के लिए सभी को आदेशित किया. इसमें किसी प्रकार की भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.जिले में लगे सभी एसएसटी पॉइंट और एफएसटी पॉइंट को प्रभावी रूप से चेकिंग सुनिश्चित कराने के लिए बताया गया. सभी एसएसटी पॉइंट्स पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे. एसएसपी ने एरिया डोमिनेशन एवम् फ्लैग मार्च और पैदल पेट्रोलिंग के लिए जिला बल एवं अर्धसैनिक बल को मिलकर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया. इसके साथ ही केंद्रीय बलों के अधिकारियों को रायपुर जिले के संबंध में ब्रीफ किया गया।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.